

कैफ़ी

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मैं कोई मुल्क नहीं हूँ कि जला दोगे मुझे
कोई दीवार नहीं हूँ कि गिरा दोगे मुझे
कोई सरहद भी नहीं कि मिटा दोगे मुझे
यह जो दुनिया का पुनरा नक्शा
मेज़ पर तुमने बिछा रक्खा है
इसमें कावाक लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं
तुम मुझे इसमें कहाँ ढूँढते हो
मैं इक अरमान हूँ दीवानों का
सख्त-जौ ख़ाब हूँ कुचले हुए इंसानों का
लूट जब हद से सिवा होती है
जुलम जब हद से गुज़र जाता है
मैं अचानक किसी कोने में नज़र आता हूँ
किसी सीने से उभर आता हूँ
आज से पहले भी तुमने मुझे देखा होगा
कभी मशरिक में कभी मगरिब में
कभी शहरों में कभी गाँव में
कभी बस्ती में कभी जंगल में
मेरी तारीख़ ही तारीख़ है,
जुग्राफिया कोई भी नहीं
और तारीख़ भी ऐसी
जो पढ़ाई तो नहीं जा सकती
लोग छुप-छुप के पढ़ा करते हैं
कि मैं ग़ालिब कभी मालूब हुआ
कालिलों को कभी सूली पे चढ़ाया मैंने
और कभी आप ही मसलूब हुआ
फर्क इतना है कि
कालिल मेरे मर जाते हैं
मैं न मरता हूँ न मर सकता हूँ।

- कैफ़ी आजमी

प्रसंगवश

अदिति रावत

कूड़े का प्रबंधन, जल संरक्षण, गोवा और हिमालय जैसे स्थानों पर पर्यटकों की बहुत अधिक भीड़-ये सभी पहलू स्थायी विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। दुनिया भर में पर्यटन आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाला मुख्य सेक्टर है, जो भारत की समृद्ध संस्कृति एवं प्राकृतिक धरोहर को बढ़ावा देते हुए आजीविका के अवसर उत्पन्न करता है।
वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार, 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन का योगदान 6.8 फीसदी यानि 256.1 अरब डॉलर था। इसी तरह दुनिया की बात करें तो 2023 में दुनिया के जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 10 फीसदी यानि 104 खरब डॉलर रहा। यह उद्योग भारत में 4.54 करोड़ लोगों को नौकरियाँ प्रदान करता है, जो भारतीय कार्यबल का 9.2 फीसदी हिस्सा बनाते हैं।
दुनिया भर में पर्यटन सेक्टर 34.8 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, यह आंकड़ा कुल कार्यबल का 10.4 फीसदी है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 1.09 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत पहुंचे, जिन्होंने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 30 अरब डॉलर का योगदान दिया। हालाँकि बड़े पैमाने पर पर्यटन के इस विकास के बीच पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है, जो जैव विविधता और संस्कृति के लिए संकट का कारण बन गया है। इस बीच पर्यटन के चलते नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए स्थायी पर्यटन की अवधारणा जोर पकड़ रही है। केप टाउन डेक्लरेशन (2002) और मैग्ना कार्टा लंदन (2020) के अनुसार स्थायी पर्यटन जिम्मेदाराना यात्रा को बढ़ावा देता है, जो धरती और लोगों दोनों के लिए फायदेमंद है। स्थायी पर्यटन के कारण पर्यावरण और संस्कृति को कम नुकसान पहुंचता है,

स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

भारत ने भी विभिन्न पहलों के माध्यम से इन विश्व स्तरीय लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जैसे 'स्वदेश दर्शन' जो पर्यावरण के अनुकूल टूरिस्ट सर्किट विकसित करता है, 'प्रसाद' जो तीर्थस्थलों के स्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है तथा 'अतुल्य भारत हरित पहल' जो स्थानीय समुदायों को समर्थन प्रदान करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देती है।

इन सब प्रयासों के बावजूद कई तरह की चुनौतियाँ हैं, खासतौर पर दूर-दराज के इलाकों में, जो प्रगति में रूकावट बन जाती हैं। जैसे कूड़े का प्रबंधन ठीक से न होना, जल संरक्षण, गोवा और हिमालय जैसे स्थानों पर पर्यटकों की बहुत अधिक भीड़- ये सभी पहलू स्थायी विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित नियमों की कमी, बाहरी लोगों और कंपनियों को आर्थिक फायदा मिलना, छोटे कारोबारों के लिए सीमित फंडिंग और समुदाय की ओर से सहयोग की कमी भी इस दृष्टि से बड़ी रूकावटें हैं। इन चुनौतियों को हल कर स्थायी पर्यटन की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए भारत को बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

समुदाय की भागीदारी और स्थानीय स्वामित्व जैसी अवधारणाएं इन समस्याओं को हल करने में कारगर हो सकती हैं। जब पर्यटन में समुदाय की हिस्सेदारी होती है, तो इसके प्रति जिम्मेदारी की भावना खुद-ब-खुद उत्पन्न हो जाती है। समुदाय अपनी संस्कृति और प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने में सबसे अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने स्थानीय संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, ताकि क्षेत्र को नुकसान न पहुंचे। इस तरह स्थानीय समुदायों की भागीदारी से लोगों

और पर्यावरण दोनों को फायदा मिलता है।

इस तरह का दृष्टिकोण जापान और स्विट्ज़रलैण्ड सहित कई देशों में सफल साबित हुआ है, जहां 'डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन' स्थानीय समुदायों को पर्यटन के संसाधनों के प्रबंधन में सक्षम बनाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि पर्यटन सेक्टर स्थानीय परम्पराओं, संस्कृति एवं पर्यावरणी क्षमता के बीच तालमेल बनाए रखते हुए विकसित होता रहे। भारत भी इसी तरह के मॉडल्स अपना सकता है, और सभी हितधारकों के लिए पर्यटन के फायदे को सुनिश्चित कर सकता है।

आर्थिक फायदों के दायरे से बढ़कर देखें तो स्थानीय लोगों की भागीदारी पर्यटन के अनुभव को बेहतर बनाती है। इसका उदाहरण है गुजरात में होडका और तेलंगाना में पोचमपल्ली, जहां स्थानीय समुदायों ने पर्यटन पर नियंत्रण रखा और अपनी पारम्परिक कारीगरी एवं जीवनशैली को बनाए रखते हुए आगंतुकों को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान किया है। इससे न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला बल्कि संस्कृति को सुरक्षित रखने में भी मदद मिली।

पर्यटन के अनुभव को बेहतर बनाकर और भीड़ प्रबन्धन की योजनाओं को लागू कर पर्यटन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। सख्त दृष्टिकोण के बजाए आसानी से स्वीकार किया जा सकने वाला प्रत्यास्थ मॉडल इस दृष्टि से अधिक उपयोगी है। इसमें पर्यटन को लेकर स्थानीय लोगों की समझ और स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्थानीय पर्यटन को आकार देने में मुख्य निर्णय-निर्माता की भूमिका निभाएं।

इसके अलावा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने से बुनियादी स्तर पर स्थायी प्रथाओं को शामिल करना आसान हो जाता है। सिक्किम का जीरो-वेस्ट टूरिज्म

मॉडल इस बात का उदाहरण है कि कैसे समुदाय स्थायित्व (सस्टेनेबिलिटी) में योगदान दे सकते हैं। इसी तरह केरल का रिस्रॉन्सिबल टूरिज्म मिशन भी समुदायिक पहलों जैसे पैपर एण्ड स्ट्रीट के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। ये सभी प्रयास पर्यटन में बदलाव लाने और स्थायित्व को बढ़ावा देने में समुदाय की भागीदारी के महत्व को दर्शाते हैं।

हाल में 11 दिसंबर को मनाये गए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम 'माउन्टेन सोल्युशन्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर' स्थानीय पर्यटन की आवश्यकता पर जोर देती है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं 'स्थायी पर्यटन समुदायों में बदलाव लाने-नौकरियाँ उत्पन्न करने, समावेशन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की क्षमता रखता है। संस्कृति एवं प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखकर यह तनाव को कम करने और सद्भावना को बढ़ाने में योगदान देता है।' यह दृष्टिकोण बताता है कि किस तरह स्थायी पर्यटन आर्थिक फायदों के दायरे से बढ़कर समुदाय में शांति एवं सद्भाव को प्रोत्साहित कर सकता है।

भारत का पर्यटन सेक्टर तेजी से विकसित हो रहा है, ऐसे में स्थायी प्रथाओं पर ध्यान देकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि पर्यटन, संसाधनों को कम करने के बजाए, उन्हें बढ़ाने और संरक्षित रखने में योगदान दे। इस दिशा में समुदाय की भागीदारी कारगर हो सकती है और पर्यटन में स्थायित्व को बढ़ावा दे सकती है। समुदाय-आधारित स्वीकार्यता दृष्टिकोण भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणी स्थायित्व के लक्ष्यों को हासिल करने में और भारत की अखंडता को बनाए रखने में उपयोगी होगा।

(डाउन टू अर्थ हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)



पीएम मोदी ने अटल जी की 100वीं जयंती पर देश की पहली केन-बेतवा राष्ट्रीय परियोजना का किया शिलान्यास

राष्ट्रीय परियोजना से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में खुलेंगे समृद्धि और खुशहाली के नये द्वार : प्रधानमंत्री

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1 वर्ष में मध्यप्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिली है। आज मध्यप्रदेश में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल



बिहारी वाजपेई के सपने को साकार करती हुई देश की पहली नदी जोड़ी परियोजना केन-बेतवा का आज यहाँ शिलान्यास हुआ है। इसके साथ ही देश के पहले प्लोटिंग सोलर पॉवर प्रोजेक्ट, ओंकारेश्वर का भी शिलान्यास हुआ है। इसके लिए मध्यप्रदेश के 'कर्मठ

मुख्यमंत्री' डॉ. मोहन यादव की सरकार और यहाँ की जनता को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत बुंदेलखंडी बोली में करते हुए कहा, 'वीरों की धरती है बुंदेलखंड पे रहबे बारे सबई जनन खों हमाई तरफ से हाथ जोड़के राम-राम पाँचे'। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश के विकास में अटल जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। वे सुशासन के प्रतीक थे। आज उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी स्मृति में मध्यप्रदेश में 1153 अटल ग्राम सेवा सदन का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, जिसकी पहली किश्त भी जारी की गई है। सुशासन हमारी सरकार की पहचान है। हमारे लिए जनहित, जनकल्याण और विकास सर्वोपरि है। हम जन सामान्य के लिए समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने देश के लिए अपना लहू बहाया था, हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए पसीना बहाते हैं। अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें लागू करना और उनका लाभ 100 प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंचाना सुशासन का पैमाना है।



बुंदेलखंड क्षेत्र ने बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष किया

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली के द्वार खुलेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष किया है, परंतु पूर्ववर्ती सरकारों ने जल संकट का कोई स्थाई समाधान नहीं निकाला। आजादी के सात दशक बाद भी राज्यों के बीच नदियों के जल के लेकर विवाद चलते रहे, परंतु उन्हें दूर करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। जब अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने नदी जोड़ी के रूप में इसका स्थाई हल निकाला और उसका कार्य भी शुरू कर दिया गया, परन्तु 2004 के बाद वह बंद कर दिया गया। आज अटल जी का नदी जोड़ने का सपना मध्यप्रदेश की भूमि पर साकार होने जा रहा है।

प्रधानमंत्री की पहल से चंबल-मालवा और बुंदेलखण्ड में होगी पर्याप्त पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेश के संदर्भ में आधुनिक युग के भगीरथ हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजा भगीरथ के प्रयासों से अवतरित हुई गंगा जी ने सभी को नया जीवन प्रदान किया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत में नए युग का सूत्रपात किया है। सकारात्मक सोच और प्रयासों से 10-12 साल में किस प्रकार परिस्थितियों में सुधार होता है, प्रधानमंत्री श्री मोदी का कार्यकाल इसका श्रेष्ठ उदाहरण है और हम सब इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी प्रकार से संपन्न वीरों की भूमि बुंदेलखंड, सूखे से सदैव प्रभावित रहा। पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्षेत्र को सूखा मुक्त करने और जल की पर्याप्त व्यवस्था करने का सपना देखा था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस सपने को धातल पर उतारने की पहल की। केन बेतवा लिंक परियोजना के शुभारंभ के साथ ही कुछ दिन पहले 35 हजार करोड़ रूपए लागत की पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना का शुभारंभ ऐतिहासिक था। इन परियोजनाओं से चंबल, मालवा और संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र को पीने का पानी एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और उद्योग-धंधों को पानी मिलेगा।



अजरबैजान से रूस जा रहा विमान कजाकिस्तान में क्रैश

42 लोगों के मारे जाने की है आशंका, 67 यात्री थे सवार, क्रैश होने से पहले इमरजेंसी लैंडिंग की मांगी थी परमीशन

अस्ताना (एजेंसी)। कजाकिस्तान के अक्ताऊ में बुधवार सुबह एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्लेन में 62 यात्री और 5 क्रू मंबरस थे। इनमें 25 लोगों को बचा लिया गया है। 22 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में 42 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। विमान अजरबैजान से रूस के चेचन्या प्रांत की राजधानी ग्रोन्जी जा रहा था।

लेकिन उसे कजाख शहर अक्ताऊ से लगभग 3 किमी दूर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एजेंसियों के मुताबिक घने कोहरे के चलते फ्लाइट का रूट बदला गया था। प्लेन ने क्रैश होने से



पहले एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए थे। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमीशन भी मांगी थी। हालांकि, बाद में उसे एयरपोर्ट के पास बीच पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। क्रैश हुआ विमान अजरबैजान एयरलाइन्स का एम्बेयर 190 मॉडल था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि विमान के क्रैश होते ही उसमें आग लग गई। कजाकिस्तान इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया कि अजरबैजान का विमान

बाकू से ग्रोन्जी के लिए जा रहा था। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। ग्रोन्जी रूस के चेचन्या इलाके में आते हैं। अजरबैजान एयरलाइन्स ने कहा है कि हादसाग्रस्त विमान एंबेयर 190 एयरक्राफ्ट था। इसकी बाकू से ग्रोन्जी रूट पर इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि ग्रोन्जी में कोहरे के कारण इसका रूट बदल दिया गया था। अजरबैजान एयरलाइन्स की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कजाकिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गईं। यह विमान अजरबैजान एयरलाइन्स का एम्बेयर ईआरजे-190 था।

बुरहानपुर में स्कूल के पास मिली अवैध हथियार की फैक्ट्री

पुलिस ने छह पिस्टल सहित 14 हथियार किए बरामद

बुरहानपुर (नप्र)। खकनार थाना क्षेत्र के पाचोरी गांव में छापा मार कर पुलिस ने फिर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। सिकलीगर सरकारी स्कूल के पास टपरी में यह फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस ने पिस्टल बना रहे पाचोरी गांव के हरविंदर सिंह जुनेजा 21 वर्ष, खरगोन निवासी प्यार सिंह 30 वर्ष और पाचोरी के एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है।

मौके से आठ पूरी तरह तैयार देसी पिस्टल, छह अर्ध निर्मित पिस्टल, नौ मैग्जीन सहित पिस्टलों के कलपुर्जे और हथियार बनाने में उपयोग होने वाले औजार बरामद किए हैं। बुधवार दोपहर एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 दिसंबर को खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव को मुखबिर् से इस फैक्ट्री के संबंध में सूचना मिली थी। वे एक निजी वाहन में सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों के साथ ठिकाने पर पहुंचे और टपरी को चारों



ओर से घेर लिया, जिससे आरोपियों को भागने का अवसर नहीं मिला। आरोपियों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के साथ संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस भी लगाई गई है। पहले भी पकड़े जा चुके हैं आरोपी- अवैध रूप से पिस्टल बनाते पकड़े गए आरोपी हरविन्द पुत्र हरबनसिंग जुनेजा निवासी पाचोरी

के खिलाफ पूर्व में खकनार थाने अवैध हथियार तस्करी का मामला दर्ज है। तब उसे छह हस्त निर्मित पिस्टल व हथियार बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी प्यारसिंग पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम गारी थाना बिस्टान जिला खरगोन के खिलाफ थाना नसरुल्लाह गंज जिला सीहोर और थाना भगवानपुरा में मामला दर्ज है।

फैक्ट्री पकड़ने में इनकी रही भूमिका

अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ने में थाना प्रभारी खकनार अभिषेक जाधव के अलावा उप निरीक्षक शिवपाल सरयाम, रामेश्वर बकोरिया, एएसआइ अशोक चौहान, अमित हनोतिया, तारक अली, प्रेमलाल पाल, महेन्द्र कुसमाकर, प्रधान आरक्षक मेलसिंह, सत्यभान, मुकेश, राजकुमार।

निखिलेश, आरक्षक मंगल पालवी, विजेंद्र, गोल्डू, जितेंद्र, आयुश, शुभम, महिला आरक्षक मीना मोरे, रजनी चौहान थाना गणपति नाका और स्वाति थाना कोतवाली की सराहनीय भूमिका रही है।

बार्डर के दो गांवों में फायरिंग से तनाव, भारी सुरक्षाबल तैनात

क्रिसमस पर भी दहला मणिपुर, जमकर उपद्रव

इंफाल (एजेंसी)। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर क्रिसमस के दिन भी भारी गोलीबारी से दहल उठा। सुरक्षा बल के सूत्रों ने बताया कि क्रिसमस के दिन राज्य की राजधानी इंफाल से सटे पहाड़ी जिलों इंफाल ईस्ट और कांगपोकपी जिलों के बीच अंतर-जिला सीमावर्ती दो गांवों में भारी गोलीबारी हुई है। हालांकि, इस गोलीबारी में कितने लोग हताहत हुए हैं,

पूर्व मुख्य न्यायाधीश का दावा, हिंसा के पीछे हैं अदृश्य ताकतें

उसकी सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है लेकिन इस घटना से इलाके में भारी तनाव है, जिसे देखते हुए प्रभावित गांवों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भेजे गए हैं। वहीं मणिपुर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मुद्गुल ने मंगलवार को कहा कि राज्य की स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है, नहीं तो यहां कुछ नहीं बचेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर को अदृश्य ताकतें जला रही हैं



न्यायाधीश अक्टूबर 2023 में कार्यकाल शुरू किया था। इसी दौरान यहां हिंसा शुरू हो चुकी थी। बीते मई तक वहां से हिंसा खबरें सामने आती रही। दिल्ली में एक फैलल चर्चा के दौरान, जस्टिस मुद्गुल ने कहा कि कुछ तत्व मणिपुर को लगातार जलते हुए रखने में अपनी रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा- मैं अब इस विचार से सहमत होने लगा हूं कि इस निरंतर हिंसा के पीछे एक अदृश्य हाथ है। यह हाथ किसका है, यह मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसके पीछे कोई कारक हो सकते हैं। आपको बता दें कि वह पिछले महीने इस अपने पद से

रिटायर हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस हिंसा को बढ़ाने में शामिल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बार जब स्थिति सामान्य होने लगती है, तो अचानक नई हिंसा की लहर आती है। इससे मुझे यह विश्वास होता है कि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं। ये ताकतें बाहरी और स्थानीय दोनों हो सकती हैं। मणिपुर में लगभग 19 महीनों से हिंसा का दौर जारी है। यहां जातीय संघर्ष का कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। हिंसा और प्रतिशोध के हमलों की इस श्रृंखला ने केंद्र सरकार को और अधिक सैनिक भेजने, अफसूरा फिर से लागू करने और विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि इन कदमों का ज्यादा असर नहीं दिखा है। मणिपुर में अब तक लगभग 240 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बार-बार राज्य में अधिक सैनिक भेजे हैं। वर्तमान में भारतीय सेना, असम राइफल्स, सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस सहित लगभग 60,000 सुरक्षा कर्मी राज्य में तैनात हैं।

नड्डा के घर ‘एनडीए’ नेताओं की बैठक

दिल्ली-बिहार के लिए तैयार हुई खास रणनीति

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल को सुसूद करना था। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री राम मोहन नायडू, किजरापु सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए।

प्रयागराज महाकुंभ से पहले ‘डरेंगे तो मरेंगे’ के होर्डिंग्स



जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने लगवाए पोस्टर

प्रयागराज (एजेंसी)। यूपी में ‘बटेंगे तो कटेंगे’ के बाद अब नया पोस्टर सामने आया है। प्रयागराज में बुधवार को महाकुंभ से पहले ‘डरेंगे तो मरेंगे’ के होर्डिंग लग गए हैं। ये होर्डिंग जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से नागावासुकी मंदिर के सामने लगवाए गए हैं। वहीं, दूसरे पोस्टर में सभी हिन्दुओं में एकता हो, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मान्तरण देश में यह कैसी छूट है। लिखा गया है। जगद्गुरु रामानंदाचार्य की ओर से लगवाए गए होर्डिंग के बैकग्राउंड में बंद मुट्ठी वाली तस्वीर की परछाई दिख रही है।

अब अंतरिक्ष में पालक उगाने की हो गई तैयारी

- इसरो का स्पेडेक्स कोशिकाएं लेकर जाएगा, 30 को लॉन्चिंग
- स्पेस डॉकिंग तकनीक वाला चौथा देश होगा भारत, उपलब्धि

श्रीहरिकोटा (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 2024 का आखिरी मिशन 30 दिसंबर को लॉन्च करने वाला है। इसे स्पेडेक्स नाम दिया गया है। स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। यह मिशन रात 9.58 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। स्पेडेक्स मिशन का मकसद अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट को डॉक और अनडॉक करने वाली तकनीक डेवलप करना और उसका प्रदर्शन करना है। दरअसल, जब कोई स्पेस मिशन लॉन्च किया जाता है तो उसके मकसद हासिल करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने होते हैं। इसके लिए अंतरिक्ष में डॉकिंग की जरूरत पड़ती है। भारत के लिए यह तकनीक मून मिशन, चंद्रमा से सैपल लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए बहुत अहम है। स्पेडेक्स मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन स्पेस डॉकिंग में सफलता हासिल कर चुके हैं। रॉकेट स्पेडेक्स मिशन के जरिए अपने साथ 200-200 किलो के 2 स्पेसक्राफ्ट लेकर जाएगा। इन्हें चेजर और टारगेट नाम दिया गया है। इनसे रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े 24 पेलोड भी भेजे जाएंगे। इन पेलोड्स को पृथ्वी से 700 किमी की ऊंचाई पर डॉक किया जाएगा। इन्हें से 14 पेलोड इसरो के और बाकी 10 स्टार्टअप और एकेडमी के हैं। इनमें से एक है- एमटी प्लांट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इन स्पेस पेलोड, जिसे एमटी यूनिवर्सिटी ने बनाया है।



संक्षिप्त समाचार

सीएम उमर के लिए खरीदी जाएंगी 3 करोड़ की कारें

- पूर्व मेयर बोले-विधायकों को सैलरी नहीं मिल रही, इनकी राजशाही कम नहीं हो रही



श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए 7 फॉर्च्यूनर और 1 रेंज रोवर कार खरीदी जाएंगी। इन 8 कारों की कुल कीमत 3 करोड़ रुपए होगी। इनमें से 4 गाड़ियां सीएम के अलग-अलग दौरे के लिए दिल्ली में रखी जाएंगी, जबकि 2 कार श्रीनगर और 2 कार जम्मू में रखी जाएंगी। राज्य सरकार की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर पूर्व मेयर जुनैद मट्टू ने कहा है कि एक तरफ विधायकों को पहली सैलरी नहीं मिली है, वहीं, दूसरी तरफ अब्दुल्ला की राजशाही कम नहीं हो रही।

संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई जारी

- एसएसआई ने कार्बन डेटिंग शुरू की, गलियारे भी मिले

संभल (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित मोहल्ला लक्ष्मणगंज प्राचीन बावड़ी कुएं का सर्वे करने बुधवार सुबह एसएसआई की टीम पहुंची। पांचवे दिन भी बावड़ी की खुदाई का कार्य जारी है। एसएसआई टीम ने



मीडिया से दूरी बनाते हुए बावड़ी कुएं की सुरंग में कार्बन डेटिंग का कार्य शुरू कर दिया है। कुएं की फोटो और वीडियोग्राफी शुरू कर दी है। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि एसएसआई की टीम बांके बिहारी मंदिर भी पहुंच सकती है।

केजरीवाल के ऐलान को दिल्ली सरकार ने ही नकारा

- कहा-मुफ्त इलाज, महिलाओं को 2100 देने की स्कीम नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की दो बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के दो विभागों ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। पहला इशतहार महिला और बाल विकास



विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। लोगों को कांड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी है।

इंदौर एयरपोर्ट पर फिर खुलेगी शराब दुकान

एक दुकान एराइवल तो दूसरी डिपार्चर एरिया में रहेगी, पहले हो चुका विरोध

इंदौर। मध्यप्रदेश के एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर शराब दुकान खोलने की कवायद इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन ने शुरू कर दी है। इस बार एयरपोर्ट पर एक नहीं, बल्कि दो दुकानें खोली जाएंगी। एक दुकान इंदौर आने वाले यात्रियों के लिए अराइवल एरिया में होगी, वहीं दूसरी दुकान इंदौर से जाने वाले यात्रियों के लिए डिपार्चर के सिक्वोरिटी होल्ड एरिया में खोली जाएगी। दोनों ही दुकानों के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने टेंडर जारी कर दिए हैं। बता दें कि पहले भी यहां एक दुकान खोली गई थी, जो की अनियमितताओं के कारण बंद हो गई थी।

20 स्कॉयर मीटर की दुकान, न्यूनतम किराया 7.25 लाख रुपए महीना

इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा जारी किए गए टेंडर 9 जनवरी को खोले जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि पहले जहां टेंडर में करीब 5 लाख रुपए महीने की न्यूनतम कीमत रखी गई थी। हालांकि टेंडर करीब 20 लाख रुपए महीने की अधिकतम बोली पर जारी किया गया था। वहीं, इस बार इसे बढ़ाकर 7.25 लाख रुपए की न्यूनतम कीमत तय की गई है। दूसरी ओर, पहले



जहां शराब दुकान के लिए कंपनी को 40 वर्ग मीटर स्थान दिया गया था, इस बार इसे घटाकर 20 वर्ग मीटर कर दिया गया है। बता दें कि एयरपोर्ट पर पहले दुकान संचालित करने वाली हिमालया ट्रेडर्स कंपनी ने 6 सितंबर 2023 को ही अपना कॉन्ट्रैक्ट सरेंडर करने का लेटर एयरपोर्ट प्रबंधन को सौंप दिया था। नियमानुसार, किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के बंद होने की सूचना मिलने पर एयरपोर्ट प्रबंधन को तुरंत दोबारा इसे शुरू करने के लिए

टेंडर जारी करने चाहिए थे। लेकिन प्रबंधन ने इसमें एक साल से अधिक का समय ले लिया। उक्त कंपनी से प्रबंधन को करीब 22 लाख रुपये हर महीने मिलते थे।

जनवरी 2024 में दुकान बंद हुई थी

इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार शराब दुकान 31 दिसंबर 2022 को एयरपोर्ट के अराइवल

एरिया में भोपाल की हिमालया ट्रेडर्स ने खोली थी। कई अनियमितताओं और शिकायतों के साथ ही टेंडर में तय राशि जमा न करने के बाद कंपनी ने 3 जनवरी 2024 से दुकान बंद कर दी थी। इसके बाद से एयरपोर्ट पर शराब दुकान नहीं थी। अब इसे दोबारा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने टेंडर जारी किए हैं। खास बात यह है कि पहली बार एयरपोर्ट पर दो दुकानें खोलने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं, जिससे आने और जाने वाले दोनों ही यात्रियों को यह सुविधा मिल सकेगी। ये दुकानें पहले की ही तरह ड्यूटी पेड शराब दुकानें होंगी।

शराब दुकान को लेकर विरोध

इससे पहले जब एयरपोर्ट पर शराब दुकान खोलने के टेंडर जारी किए गए थे, तब शहर के कई सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने देवी अहिल्या के नाम पर बने एयरपोर्ट में शराब बेचने को लेकर कड़ा विरोध जताया था। हालांकि, प्रबंधन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के हर एयरपोर्ट में यह सुविधा होने की बात कहते हुए इस विरोध को खारिज कर दिया था।

इंदौर का आईएसबीटी नए साल में होगा शुरू

100 करोड़ की लागत से तैयार, यूपी-राजस्थान-गुजरात की बसों का होगा संचालन



आधुनिक सुविधाओं से लैस परिवहन का अनुभव मिलेगा।

कुमेड़ी स्थित आईएसबीटी बनकर लगभग तैयार है- कुमेड़ी में बनने वाले आईएसबीटी को यात्रियों और ट्रेवल संचालकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इस नए बस टर्मिनल का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया जाएगा, जिससे इंदौर के सार्वजनिक परिवहन में एक नई क्रांति आने की उम्मीद है। ट्रेवल संचालकों के लिए अलग ऑफिस और स्टाफ सुविधाएं ड्राइवर-कंडक्टर और अन्य स्टाफ के लिए

अलग बिल्डिंग।रेस्ट रूम, पीने के पानी और टॉयलेट की सुविधा। ट्रेवल संचालकों के लिए 32 ऑफिस तैयार।100 करोड़ की लागत से विकसित। यात्रियों के लिए खास इंतजाम 14 टिकट काउंटर। आसान टिकट बुकिंग के लिए। 43 प्लेटफार्म। यात्रियों के बैठने और उतरने की सुविधा। बसों की पार्किंग और अलग-अलग आने-जाने की व्यवस्था। रेस्तरांत, एटीएम और 32 अन्य दुकानों का प्रावधान। कुमेड़ी का नया बस स्टैंड, जिसे सितंबर 2019 में मंजूरी मिली थी, पहले दिसंबर 2022 तक पूरा होना था।

इंदौर में महिला ने पुलिस कर्मी का कॉलर पकड़ा

खजराना मंदिर में हंगामा, गार्ड ने घसीटते हुए बाहर निकाला, बच्चों को ले जाने का आरोप



इंदौर। इंदौर के खजराना मंदिर में बुधवार को महिला ने हंगामा करते हुए एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया। यहां से महिला को थाने ले जाया गया। पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की बात कही है। टीआई मनोज सेंधव के मुताबिक, मंदिर के अन्न क्षेत्र में महिला ने दो बच्चों को रोका। उनसे पूछताछ करने लगी। बच्चों ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी, जो मंदिर में ही गई है। गार्ड ने महिला पर बच्चों को ले जाने का आरोप लगाया। महिला को वहां मौजूद पुलिसकर्मी के पास ले गए। यहां महिला ने हंगामा कर दिया। इसके बाद महिला को सुरक्षा गार्ड ने पकड़कर घसीटते हुए बाहर की तरफ किया। टीआई के मुताबिक, महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसके परिवार की जानकारी निकाली जा रही है।

कांग्रेस ने सांसद को भेंट की संविधान की किताब

शंकर लालवानी से पूछा- क्या आप अमित शाह के बयान से सहमत हैं



इंदौर। कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को इंदौर सांसद शंकर लालवानी को संविधान की किताब भेंट की। उनसे पूछा कि क्या आप अमित शाह के बयान से सहमत हैं। जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पूरे देश में हर वर्ग, हर संप्रदाय इसका विरोध कर रहा है। दरअसल, 17 दिसंबर को शाम 7:45 बजे राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है। अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते, तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।

इंडोनेशिया के संत डॉ. ई. मादे धर्मयश इंदौर आए

इंदौर। बाली (इंडोनेशिया) के संत रसाचार्य डॉ. ई. मादे धर्मयश जी इंदौर आए। साहित्यकार, समाजसेवी डॉ. बनवारी लाल जाजोदिया यथार्थ के आतिथ्य में आए डॉ. ई. मादे धर्मयश जी ने उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इसके साथ ही इंदौर के सभी प्रमुख मंदिर, राजवाड़ा देखकर काफी खुश हुए। मालवा की दाल बाटी, बाफला, उज्जैन में मक्का, बाजरा, ज्वार की रोटी उन्हें बहुत पसंद आई। इंदौर से वे खजुराहो के लिए रवाना हुए और मग्न के अन्य शहरों से होते हुए प्रयागराज महकुंभ पहुंचेंगे। इस बीच, बाली के संत रोहरी क्लब ऑफ इंदौर के नंदकिशोर उपाध्याय के यहां आयोजित पारिवारिक मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने आशीष वचनों में उन्होंने कहा कि मानव जीवन ही औरों का प्रोपकृषण करने के लिए ही मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दें। उनका कलब की ओर से शाल, श्रीफल, मोतियों की माला से क्लब अध्यक्ष हर्षवर्धन दीक्षित, उपाध्याय, डॉ. जाजोदिया तीनों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन आकाश अग्रवाल ने किया।

इंदौर में फिर अवैध बाड़ों के खिलाफ ऐक्शन

दो बाड़ों को तोड़ा, हिन्दू संगठनों में नाराजगी



इंदौर। इंदौर में फिर पशु पालन शुरू हो गया है और अवैध बाड़े भी बनने लगे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ फिर नगर निगम ने कर्मर कसी है। बुधवार को सुबह दो बाड़े रिमूवल गैंग ने तोड़े और 50 से ज्यादा मवेशियों को मुक्त कराया। शहर में 30 से ज्यादा अवैध बाड़े अफसरों ने चिन्हित किए हैं। जिन्हें नगर निगम तोड़ेगा और पशु पालकों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करेगा। बुधवार सुबह नगर निगम की टीम दत्त नगर पहुंची। यहां सार्वजनिक जमीन पर अवैध बाड़ा बनाकर पशुपालन हो रहा था। रहवासियों ने इस बाड़े को लेकर शिकायत की थी कि रात के समय यहां अस्वामाजिक तत्व आते थे और

नशाखोरी करते थे। बाड़े पर बुलडोजर चलाने से पहले अफसरों ने 30 पशु वाहन में रखवाए और उन्हें गौशाला भेजा गया। इसके बाद बुलडोजर से बाड़ा तोड़ा गया। इसके बाद सूर्यदेव नगर में दूसरा अवैध बाड़ा तोड़ने अमला पहुंचा और वहां से 20 पशु मुक्त कराकर यशवंत सागर गौशाला पहुंचाए गए। इसके बाद दूसरा बाड़ा भी तोड़ा गया। आपको बता दें कि तीन साल पहले इंदौर पशु मुक्त हो गया था और धारा -144 लगाकर पशु पालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन फिर धीरे-धीरे अवैध पशु पालन शुरू हो गया। हिन्दू संगठनों ने की तोड़फोड़- नगर निगम ने अवैध बाड़े तोड़ने का विरोध भी

हुआ। बाड़े पर बुलडोजर चलाने से पहले अफसरों ने 30 पशु वाहन में रखवाए और उन्हें गौशाला भेजा गया, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ट्रक रोक कर उसमें तोड़फोड़ कर दी।

निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। इससे निगम कर्मचारी भी नाराज हो गए और उन्होंने हवा बंगला जोन पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मारपीट के कारण तीन निगमकर्मि घायल हुए हैं। हिंदू संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि पशुओं को गलत तरीके से गाड़ी में डाला गया। गौशाला में पशुओं की देखभाल की जा रही थी। गौशाला को बैगर नोटिस के तोड़ा गया।

इंदौर सहित मग्न की मंडियों में घटी कपास की आवक

2 हजार गांठ कम होकर 18 हजार पर पहुंची

इंदौर। मध्यप्रदेश की मंडियों में कपास की आवक 2 हजार गांठ कम होकर 17 हजार से 18 हजार गांठ की रही। आवक में गिरावट के बावजूद कपास के भाव स्थिर हैं। कॉटन सीड में भी स्थिरता है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों के प्रभाव से 75 आरडी कॉटन कैंडी में तेजी रही। नए कपास की आवक 17000 (-2000) से 18000 (-2000) गांठ (एक गांठ =170 किलोग्राम) की रही। कपास के भाव 6000 से 7300 रुपए प्रति किंटल पर स्थिर रहे। कॉटन सीड भी 2900 से 3150 रुपए प्रति किंटल पर स्थिर हैं। मिलर्स के अनुसार बेहतर क्वालिटी के कपास में मांग बनी हुई है। सीसीआई द्वारा बड़े पैमानों पर किसानों का कपास निरस्त किया जा रहा है, जो कि मंडियों में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके



चलते मिलर्स द्वारा भी बेहतर खरीदारी की जा रही है। जानकारों के अनुसार मध्यप्रदेश की

मंडियों में व्यापारियों द्वारा कपास की कीमत एमएसपी के स्तर से कम ही रही है। मग्न में 9व नमी वाले 73 आरडी कॉटन के भाव अपने पूर्व स्तर 52000 से 52200 रुपए प्रति कैंडी (1 कैंडी=356 किलोग्राम) पर स्थिर रहे हैं। वहीं, मग्न में 9व नमीयुक्त 75 आरडी कॉटन के भाव भी तेजी है। 75 आरडी कॉटन के भाव निचले स्तर पर 300 और ऊपर के स्तर पर 200 रुपए बढ़कर 53000 (+300) से 53400 (+200) रुपए प्रति कैंडी पर रहे हैं। 75 आरडी कॉटन में सोमवार को भी 200 रुपए की तेजी आई थी। इस प्रकार दो कारोबारी क्षेत्र के दौरान इसके भाव 500 से 400 रुपए तक बढ़ गए हैं।

भिक्षुकों ने घेरा कलेक्टर कार्यालय, 5 हजार रुपए महीना मांगा

इंदौर। इंदौर में कलेक्टर द्वारा शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की मुहिम के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी संख्या में भिक्षुक, दिव्यांग और कुछ पीड़ित कलेक्टर कार्यालय पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें भिक्षा मांगने की अनुमति दी जाए या उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा पेंशन के नाम पर दिए जा रहे 600 रुपए और राशन से उनके परिवार का गुजारा संभव नहीं है। प्रदर्शन में शामिल कुछ पीड़ितों और भिक्षुकों ने संघ का निर्माण कर लिया है, जिसमें सहयोग कुछ निवारण संघ और दिव्यांग हितग्राही भी शामिल हैं। संघ के अध्यक्ष सारंग गायधने और सुभाष भरवाड़ ने बताया कि उनका जीवन भिक्षावृत्ति पर निर्भर है, और कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा 1 जनवरी से भिक्षा देने और लेने वालों पर एकआईआर दर्ज करने के आदेश उनके जीवनयापन के अधिकार का हनन है।



सहायता की मांग की

कलेक्टर द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल रसोई योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र पांच रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मजदूर चौराहों और रैन बसेरों पर भी यह सुविधा नगर निगम द्वारा दी जा रही है। शहर की कई सामाजिक संस्थाएं भी इसी तरह की योजनाओं में योगदान दे रही हैं। परदेशीपुरा क्षेत्र में साई मंदिर समिति द्वारा भी पांच रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध

कराया जा रहा है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने प्रति माह 5 हजार रुपए की सहायता राशि की मांग की। उन्होंने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि आंध्रप्रदेश में 6 से 15 हजार रुपए, दिल्ली और हरियाणा में 3 हजार रुपए, और महाराष्ट्र में 4 हजार रुपए मासिक सहायता दी जाती है। इंदौर में भी कम से कम 5 हजार रुपए मासिक सहायता की मांग की गई।

कलेक्टर कर रहे रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था

कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट जवाब दिया कि शहर में भिक्षावृत्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निसहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए उज्जैन के सेवाधाम में इलाज और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही, हातोद के पास पिपु पर्वत क्षेत्र में कुछ रोगियों को घर और खेती के लिए जमीन भी दी गई है। कुछ रोगियों का कहना है कि पेंशन और राशन की मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

संपादकीय

खेल रत्न पर अप्रिय विवाद

देश के आइकन खिलाड़ी मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने को लेकर मचा विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंता की बात यह है कि देश के इस सबसे बड़े खेल पुरस्कार को लेकर तकरीबन हर साल कोई न कोई विवाद होता रहता है। योग्य व्यक्ति को पहले अनदेखा किया जाता है और हल्ला मचने पर उसे पुरस्कार दे दिया जाता है। कहना मुश्किल है कि ऐसा किसी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है अथवा पुरस्कार देने के लिए जिन लोगों को बिठाया गया है, उनकी समझ और क्षमता ही कम है। इसमे दो राय नहीं कि एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली अकेली भारतीय शूटर मनु भाकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वथा योग्य हैं। फिर भी उनका नाम पुरस्कार के लिए नामांकन सूची में न होना खेल प्रेमियों को आहत कर गया। ऐसा क्यों हुआ, जानबूझकर अथवा नासमझी के कारण, इसका जवाब अभी मिलना है। जब मीडिया में यह मामला उलझा तो लीपापोती की जा रही है। मनु भाकर के दुखी पिता ने तो यहां तक कह दिया कि बेहतर है कि लोग अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने की बजाए आईएसए बनाएं। गौरतलब है कि सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि 12 सदस्यीय पुरस्कार समिति ने खेल रत्न के लिए जिन नामों की सिफारिश की है, उनमें मनु भाकर का नाम शामिल नहीं है। जबकि इस साल पेरिस में हुए ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्सड एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। साल 2021 में मनु भाकर ने 'बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ़ द ईयर 2020' अवॉर्ड जीता था। विवाद बढ़ने पर मनु भाकर ने बयान दिया कि उसका पहला लक्ष्य खेल में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतना है न कि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करना। हालांकि मनु ने यह भी कहा कि संभव है कि उससे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किए गए नामांकन में कुछ त्रुटि हो गई होगी। जिसे अब ठीक कर लिया गया है। वैसे तो इतने नामी खिलाड़ी, जिनकी उपलब्धियां सर्वज्ञात हैं, को पुरस्कार के लिए आवेदन करना पड़े, यह बहुत जंचने वाली बात नहीं है। यूं भी खेल की उपलब्धियां कांच की तरह साफ होती हैं। उन्हीं को आधार मानकर पुरस्कार समिति को निर्णय लेना चाहिए। यही नहीं, सवाल तो पुरस्कार समिति पर भी है। बताया जाता है कि इस बार पुरस्कारों की सिफारिश करने वाली समिति में ओलंपिक खेलने वाला सिर्फ एक सदस्य था जबकि सभी ब्यूरोक्रेट्स थे। उन्हें खेल उपलब्धियों की कितनी समझ होगी, समझा जा सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मनु पिछले तीन-चार साल से इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर रही थीं, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन इस बार तो मनु की पुछा दावेदारी बनती है। एक चर्चा यह भी है कि ओलंपिक में दो मेडल जीतने के बाद मनु गांधी परिवार से मिली थी, इसलिए भी उसका नाम नामांकन सूची में शामिल नहीं किया। अगर ऐसा है तो यह बहुत संकीर्ण सोच है। खेल पुरस्कारों को भी राजनीतिक दृष्टि से देखना सही नहीं है, क्योंकि खेलों में उपलब्धि राजनीतिक प्रतिबद्धता या जोड़-तोड़ से नहीं मिलती। सप्टा में जो जीतता है, वह सबके सामने पड़ता है और ऐसा करने के लिए खिलाड़ी को भारी पसीना बहाना होता है, रात-दिन मेहनत करनी होती है, कई बार भौतिक सुखों को भी ताक पर रखना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि खेल पुरस्कारों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ हो ताकि मनु भाकर जैसे अप्रिय विवादों पर लगाम लगे।

नजरिया

अशोक भाटिया

लेखक आर्थिक विश्लेषक हैं।



नए साल 2025 का आगमन कई उम्मीदों के साथ होगा। ऐसे में आगामी बजट से वरिष्ठ नागरिकों को खास उम्मीदें हैं। पिछले साल पेश बजट में वित्तमंत्री ने सीनियर सिटीजंस के लिए कई बड़ा प्लान नहीं किया था। इसलिए सीनियर सिटीजंस को आने वाले बजट से ज्यादा उम्मीदें हैं,ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके बटुए में और ज्यादा पैसे आएंगे या नहीं। इस समय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट पर काम शुरू कर दिया है सो अभी से सीनियर सिटीजन ने अपनी तकलीफों व मांग को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पीएम आने वाले युनियन बजट 2025 के लिए उनकी राय और सुझाव लिए हैं। दु:ख इस बात का है कि किसी भी सीनियर सिटीजन को उनकी तकलीफों व राय जानने के लिए नहीं बुलाया जाता ।

इनकम टैक्स क़ानून के अनुसार, सीनियर सिटिज़न्स को दो समूहों में बांटा गया है- सीनियर सिटिज़न्स और सुपर सीनियर सिटिज़न्स। इनमें से प्रत्येक समूह के लिए टैक्स सम्बंधी क़ानून भी अलग-अलग हैं। सीनियर सिटिज़न्स यानी 60 से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए 3 लाख रुपये की इनकम तक टैक्स माफ़ है। सुपर सीनियर सिटिज़न्स यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये की इनकम तक टैक्स माफ़ है। रिटायर्ड लोग चाहते हैं कि यह अंतर ख़त्म हो जाए क्योंकि कई लोगों के पास, पेंशन और इन्वेस्टमेंट को छोड़कर इनकम का कोई अन्य साधन नहीं है। उनका मानना है कि सबके लिए 5 लाख रुपये की छूट सीमा तय की जानी चाहिए ताकि सभी सीनियर सिटिज़न्स पर टैक्स का बोझ कम हो सके।मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार, सीनियर सिटिज़न्स को अलग-अलग रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है।

सीनियर सिटीजंस को उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण हेल्थ इश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ा सकती हैं। अभी 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर सालाना 50,000 रुपये डिडक्शन की इजाजत है। बुजुर्गों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में खासकर कोविड की महामारी के बाद हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम काफी बढ़ गया है। इसलिए सरकार को 50,000 रुपये के डिडक्शन को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये कर देना चाहिए। इससे उन पर टैक्स का बोझ घटेगा ।

सीनियर सिटिज़न्स पर महंगाई का ज्यादा असर पड़ता है। उनके इनकम के साधन सीमित और अक्सर निश्चित होने के कारण, बढ़ती महंगाई के कारण सीधे तौर पर उनकी खरीदने की ताकत कम हो सकती है। उनके पास महंगाई से लड़ने के लिए अपने इनकम को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं

नए साल और नए बजट से बंधी बुजुर्गों की उम्मीदें

इनकम टैक्स कानून के अनुसार, सीनियर सिटिज़न्स को दो समूहों में बांटा गया है- सीनियर सिटिज़न्स और सुपर सीनियर सिटिज़न्स । इनमें से प्रत्येक समूह के लिए टैक्स सम्बन्धी कानून भी अलग-अलग हैं । सीनियर सिटिज़न्स यानी 60 से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए 3 लाख रुपये की इनकम तक टैक्स माफ़ है । सुपर सीनियर सिटिज़न्स यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये की इनकम तक टैक्स माफ़ है । रिटायर्ड लोग चाहते हैं कि यह अंतर ख़त्म हो जाए क्योंकि कई लोगों के पास, पेंशन और इन्वेस्टमेंट को छोड़कर इनकम का कोई अन्य साधन नहीं है । उनका मानना है कि सबके लिए 5 लाख रुपये की छूट सीमा तय की जानी चाहिए ताकि सभी सीनियर सिटिज़न्स पर टैक्स का बोझ कम हो सके ।



भी हो सकता है। इसलिए, सरकार उन्हें अधिक से अधिक, महंगाई को मात देने वाले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देने के बारे में सोच सकती है। वर्तमान में, सीनियर सिटिज़न्स सेविंग्स स्कीम में 30 लाख रुपये तक इन्वेस्ट किया जा सकता है जिस पर 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। सरकार इस सीमा को बढ़ाने, ज्यादा रेट ऑफ़ रिटर्न देने और एक कम लॉक-इन फिक्स करने के बारे में सोचना चाहिए । इससे सीनियर सिटिज़न्स की खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी और उन्हें बेहतर लिक्विडिटी मिल पाएगी।

कई सीनियर सिटीजन की मांग है कि उन्हें चालू ब्याज से 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मिलना चाहिए । वरहाई पूर्व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के आनंद बोंगिरवार के अनुसार सरकार वरिष्ठ नागरिकों का बैंक में जमा पूंजी की पुरी राशी की सुरक्षा की गारंटी करें इसे 5 लाख की सीमा में लॉक अप न किया जाय । देश में चल रहे सभी विमान सेवा नागरिकों को 50 प्रतिशत डिस्काउंट प्रदान किया जाये, विमान सरकारी हो यां गैर सरकारी । इस समय पारिवारिक पेंशन के लिये 80 लाख लोग पेंशन के लिये लगातार संघर्ष कर रहे है सभी वरिष्ठ नागरिक को पेंशन प्रदान किया जाय क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल मे बहुत ही कम पैसे मे गुजर किया था और महंगाई बढ़ने पर उनकी कमा पूंजी में

कमी हो गई है। इसी प्रकार सीनियर सिटीजन को दांतों की बीमारी के लिए इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। नकली दांत बनवाने, और दांतों का इलाज करने की इनकम टैक्स में छूट दी जावे। दांतों के इलाज में एक बड़ी धनराशि खर्च होती है। मोदी सरकार ने चुनाव के पहले वायदा किया था कि 70 वर्ष से उमर के हर वर्ग के सीनियर सिटीजन को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा वह कार्यान्वित हो रहे रहा है पर सीनियर सिटीजन कि मांग है कि उम्र सीमा घटा कर 70 से 60 वर्ष की जाय तथा यह आयुष्मान कार्ड गिने चुने सरकारी हॉस्पिटल में काम आता है, यदि यह सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लागू हो तो इसकी सार्थकता होगी ।

कोविड से पहले तक सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर 40 से 50 फीसदी तक की छूट दी जाती थी लेकिन ये छूट कोविड के समय खत्म कर दी गई। कोविड का डर देश और दुनिया में खत्म होने के बाद भी सरकार ने इस छूट को फिर से शुरू नहीं किया है। अब सीनियर सिटीजन बजट में ट्रेन टिकट पर 50 फीसदी तक की छूट दिये जाने की डिमांड कर रहे हैं। वह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें ये छूट फिर से देना शुरू करेंगे।गौरतलब है कि आईआरसीटीसी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी केटेगरी में रियायती किराए ऑफर करता था। आईआरसीटीसी साल 2019 के अंत तक 60 साल से

अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिला बुजुर्ग यात्रियों को दुरंतो, शताब्दी, जन शताब्दी, राजधानी, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के ट्रेन टिकटों पर किराए में छूट देता था। जहां पुरुष वरिष्ठ नागरिक 40 प्रतिशत की रियायत के पात्र थे, वहीं महिला वरिष्ठ नागरिक ट्रेन टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकती थीं। साल 2019 के अंत तक सीनियर सिटीजन को ट्रेनों की टिकट की कीमत पर 40 से 50 फीसदी तक की छूट मिली थी। अगर राजधानी का फर्स्ट एसी का टिकट 4,000 रुपये है तो सीनियर सिटीजन को 2,000 या 2,300 रुपये में मिलता था। फिर साल 2019 के अंत और साल 2020 की शुरुआत में कोविड देश और पूरी दुनिया में फैल गया जिसके बाद आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग बिंडो पर ये सर्विस मिलनी बंद हो गई। अब सीनियर सिटीजन उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में उन्हें ये खास छूट फिर से मिलेगी। सरकार को ऐसे सीनियर सिटीजंस को घर के किराए पर टैक्स डिडक्शन देना चाहिए, जिनकी रगुलर इनकम नहीं है। इससे बुजुर्गों पर टैक्स का बोझ कम होगा। उन्हें उम्मीद है कि वित्तमंत्री इस बार बजट में उनकी यह मांग पूरी करेंगी।

वर्तमान में, मूल कर छूट सीमा वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के लिए 3 लाख रुपये और बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए 5 लाख रुपये है। यह वह सीमा है जिस तक वरिष्ठ नागरिक की आय पर कर नहीं लगता है। अब, मांग यह है कि बजट में नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के लिए मूल कर छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए, जो कि बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के समान है।

वरिष्ठ नागरिक आगामी 2025 बजट में संभावित बोनस योजनाओं और कर प्रोत्साहनों को लेकर आशांचित हैं। यह उम्मीद बुजुर्ग आबादी के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर आधारित है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किए गए बोनस धन का सीधा इंजेक्शन प्रदान करना संभव है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, दैनिक जीवन और अन्य आवश्यक खर्चों से जुड़ी बढ़ती लागत को संबोधित करने में मदद मिलेगी। इससे न केवल वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता मिलेगी।

प्रशासन

प्रियंका सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।



भारतीय शासन व्यवस्था को अक्सर 'लोगों की कमी' लेकिन 'प्रक्रियाओं की कमी' के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कि प्रभावी शासन के लिए उपलब्ध बड़ी प्रशासनिक मशीनरी और सीमित मानव संसाधनों के बीच असंतुलन को दर्शाता है। जबकि नौकरशाही प्रक्रियाएँ अच्छी तरह से स्थापित हैं, कर्मियों की कमी कुशल कार्यान्वयन में बाधा डालती है। यह विरोधाभास देरी, अक्षमताओं और अपर्याप्त सार्वजनिक सेवा वितरण का कारण बनकर शासन को प्रभावित करता है, जिससे नागरिकों की जरूरतों के प्रति राज्य की जवाबदेही कम होती है। शासन व्यवस्था को 'लोगों की कमी' लेकिन 'प्रक्रियाओं की कमी' के रूप में वर्णित किया जाता है। भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या कम है, जिसके परिणामस्वरूप जटिल शासन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कर्मियों की कम उपस्थिति है। भारत में प्रति मिलियन केवल 1,600 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि अमेरिका में प्रति मिलियन 7,500 हैं, जिससे राज्य की दक्षता प्रभावित होती है। कम सिविल सेवकों के बावजूद, नौकरशाही लाइसेंसिंग, परमिट और मंजूरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं में फंसी हुई है। व्यवसाय शुरू करने के लिए मंजूरी, परमिट और अनुमोदन की भूलभुलैया से गुजरना पड़ता है जो प्राप्ति में बाधा डालते

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ़्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी

संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय

वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल

स्थानीय संपादक - हेमंत पाल

प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे सम्बाध पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

कर्मचारियों की कमी से जूझती शासन व्यवस्था

हैं और परियामों में देरी करते हैं। भारतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पुलिसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कर्मचारी हैं, जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व में 22,000 कर्मचारी हैं, जो राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के प्रबंधन में प्रभावशीलता को सीमित करता है। नीति-निर्माण अत्यधिक केंद्रीकृत है, लेकिन कार्यान्वयन सीमित

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजनाओं को क्रियांचित करता है, जबकि नीति निर्माण मंत्रालय स्तर पर रहता है, जिससे देरी और लागत में कमी आती है। सरकारी कर्मचारियों का छोटा आकार अधिकारियों पर अत्यधिक बोझ डालता है, जिससे प्रभावी नीति निष्पादन मुश्किल हो जाता है। अपर्याप्त जनशक्ति और अत्यधिक प्रक्रियाओं के कारण सेवाओं में देरी होती है, क्योंकि अधिकारी काम की मात्रा को संभालने के लिए संघर्ष करते हैं। बोझिल विनियामक मंजूरी और अग्रिम पॉक के निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की कमी के कारण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को लागत में वृद्धि और देरी का सामना करना पड़ता है। नीति निर्माण और निष्पादन का विभाजन निर्णय लेने वालों और सेवा कार्यान्वयनकर्ताओं के बीच एक विभागे पैदा करता है, जिससे खराब प्रदर्शन के लिए जवाबदेही कम हो जाती है। जब सड़क निर्माण परियोजनाओं में समस्याएँ आती हैं, तो मंत्रालयों और कार्यान्वयनकर्ताओं के बीच निगरानी के लिए स्पष्ट

जिम्मेदारी की अनुपस्थिति के कारण दोषारोपण और अक्षमताएँ होती हैं। सरकार के भीतर कौशल की कमी के कारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निजी परामर्श फर्मों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे सार्वजनिक व्यय बढ़ जाता है। भारत सरकार ने उन कारणों के लिए परामर्श शुल्क पर 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए, जिन्हें बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों के साथ घर में ही प्रबंधित किया जा सकता था। नौकरशाही की जटिल



प्रक्रियाएँ जॉखिम लेने और विवेकाधीन निर्णय लेने से परहेज पैदा करती हैं, जिससे नवाचार बाधित होता है और अनुकूलन धीमा होता है। उच्च सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन और नौकरी की सुरक्षा के साथ प्रोत्साहनों का गलत संरेखण ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो सामाजिक सेवा के बजाय वित्तीय लाभ से प्रेरित होते हैं। लोगों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर योग्य पेशेवरों की भर्ती बढ़ाएँ, जिससे कुशल कार्यबल सुनिश्चित हो। मिशन कर्मयोगी जैसे पारस्व प्रवेश कार्यक्रम और विशेष प्रशिक्षण पहल सिविल सेवकों के कौशल और दक्षता में सुधार कर सकते हैं। कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेने, जवाबदेही में सुधार और प्रक्रियाओं को गति देने के लिए प्रत्यायोजित अधिकार के साथ फ्लैटलाइन कर्मियों को सशक्त बनाएं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समान नीतियों को क्रियांचित करने में फ्लैटलाइन कार्यकर्ताओं को अधिक नियंत्रण देने से देरी

व्यंग्य

डॉ. महेंद्र अग्रवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।



लाठी से लड़ने वाले को लठैत या लड्डवाज कहा जाता है। ये लाठी चलाने में विशेषज्ञ की हैसियत रखते हैं। पहले लड़ाई झगड़ों में इन्हें किराये पर बुलाया जाता था।ये हथियार करने वाले को उसका अच्छ रिटर्न भी देते थे।एक एक लठैत दसियों को धूल चटा देता था।गंव देहातों में इनकी बड़ी धूम है। घर का बंटवारा हो, किसी का खेत जोतना हो, बगलवाले की जमीन पर मकान बनाना हो, पड़ोसी का हिसाब चुकता करना हो तो इनकी जरूरत पड़ ही जाती है। इससे गैरकानूनी काम में भी कानून अपनी टांग नहीं अड़ता। वैसे भी लठु हमारी प्राचीन संस्कृति का अविभाज्य अंग है। कहा भी जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोकतंत्र में लठु गांधी जी की लाठी की तरह नब्बे छड़ी पर खड़ा रहता है।

लोकतंत्र से लड्डतंत्र की ओर अग्रसर हम

मजबूत हाथों का सहारा लिये हुए जिसे देखकर ही कमजोर दिल वालों की फूँक सरक जाती है। कुछ तो दर्शन मात्र से अपने पंचों की वापिसी के लिए निर्वाचन कार्यालय की दौड़ लगा देते हैं। इससे लोकतंत्र मेरा मतलब लड्डतंत्र के बैठने या लेटने की नौबत कभी नहीं आती।

आजुबी के बाद देश का विकास हुआ हो अथवा न हुआ हो परन्तु लोकतंत्र को विकास के सोपानों पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सका। सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रमुख सेवादारों ने मूक समर्थन के साथ सामूहिक रूप से लोकतंत्र को विकास करने का बोझ उठा लिया है। इसी का सुपरिणाम है कि हम अब लोकतंत्र से लड्डतंत्र की ओर अग्रसर हैं। पहले चुनावों में बूथ लूटे जाते थे।मुंह पर फेंटा लगाये बंदकुधारी हथियार करते पड़ते थे।अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता और बंगाल के जादू की तरह खेत या खेला हो जाता है।

समय और विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत से नए तरीके चल निकले हैं। जहाँ-जहाँ विरोधी प्रत्याशी भारी पड़ता है वहाँ उसे या

उसके वज़नदार कट्टर समर्थक की लाटरी खुलवाने या उसे जीते जी परमश्राम पहुँचाने की सेवायें शुरू हो गई हैं। बस स्थानीय स्तर पर कल्याणकारी व्यक्ति प्रशासन की नाक में नकेल डालने वाले दल से जुड़ा हो।या यूँ कहें प्रशासन मेहरबान तो ई वी एम पहलवान है। लठु के प्रताप से ही हर चुनाव में मतदान के बाद सरकारी गाड़ियों में ई. वी.एम मशीनों पाई जाती हैं। होने को ये रिजर्व वाली होती है खाली ,मगर बात का बगड़ बनाने वाले विरोधी इसे बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने में देर नहीं करते। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर। जिस चुनाव में ये कहीं नहीं मिलतीं वहाँ पुरानी वीडियो क्लिप चलाकर काम चलाया जाता है। अब ये भी ई. वी. एम. जितनी रहस्यमयी बात है कि ऐसा सत्तारूढ़ दल को सुखी व संतुष्ट करने के लिए होता है या खालियाँ बंदनाम करने के लिए हर बार, बार-बार यही कहनी क्यों सामने आती है?

चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? वे ई.वी.एम. की महता को

भी समझते हैं। फिर भी वे उसे अपनी सरकारी गाड़ी में भरकर इधर-उधर घूमते रहते हैं। कोई घर खाना खाने आ जाता है तो कोई थकान से परेशान होकर होटल में आराम करने। वास्तव में ये देशक प्रभारियों को मतदान केन्द्र पर डीवीएम खराब होने को सकार में बदलने के लिए दी जाती हैं किन्तु वे इसे अपनी प्राइवेट प्रोपर्टी समझकर तफरीह करते रहते हैं। सरकारी आदमी हैं ना इसलिए इनका रुट बदलकर इधर उधर होना शक पैदा करता है मगर वे कहते हैं कि बीमार आदमी क्या डॉक्टर को दिखाने भी न जाये अगर उनकी वजह से लोकतंत्र की सेहत खराब हो रही हो तो हो जाये तो क्या उसके लिए मर जायें।

इधर नए भारत में लडु या लड्डवाजी भी रूप परिवर्तन को बाध्य हुई है। गठबंधन में एक दल दस सीट मागे और उसे एक भी सीट न देकर जब दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दे तो इसे भी लड्डमारी ही कहा जायेगा। जिसे मंत्रीमंडल की आस हो और जगह न मिले तो वह भी बिना लडु मारे जमीन सूँसता दिखाई देता है। किसी सरकारी विभाग द्वारा पैसे खाने वाले पत्रकारों की गोपनीय सूची जारी करना भी लड्डमारी का बेहतरीन उदाहरण है। और ये कुछ भी नहीं है इल्लुकी मात्र है। सौ साल पूरे होने दीजिये फिर देखिये कि लड्डमारी के कैसे-कैसे उदाहरण सामने आते हैं।

विचार

जवाहर चौधरी

लेखक साहित्यकार हैं।



अनेक लेखक जिन्हें टेबल पर होना चाहिए, नारायण-नारायण करते हिंदी साहित्य के व्योम मार्ग में विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। देवण भी अपनी सत्ताओं-सेनाओं के साथ वो सब करने में व्यस्त हैं जिसका प्रायः वे ही विरोध करते रहे हैं। एक पीढ़ी है जिसने साहित्य के बड़े संसार को रचने में अपना योगदान दिया। साहित्य का इतिहास खंगालेंगे तो वे उसमें दर्ज भी मिलेंगे। भगवान आज बुला भी ले तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चढ़ी हुई पतंग ऐसे ही कोई कैसे छोड़ सकता है। उड़ रही है तो उड़ने दो मजे में। कहीं किसी बहस-गोष्ठी में नवोदित चिंता करने लगते हैं कि हिंदी का पाठक गुम हो रहा है तो उन्हें सुनना ही पड़ता है। किताबें छप तो बहुत रही हैं लेकिन पढ़ने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप चरिछों ने लिखा तो हमने पढ़ा, अब हम लिख रहे हैं तो कड़ी आगे जुड़ नहीं रही है। यही हाल रहे तो हमें पुस्तकालयों में ही सड़ जाना पड़ेगा! वो तो भला हो कमीशनखोरों का जो खरीद रहे हैं, वरना पुस्तकालय भी नसीब नहीं होता। सबका बाजार है एक हिंदी साहित्य का ही नहीं बन पा रहा है। नवोदितजी के तीन बच्चे हैं और तीनों अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे पैतालीस-पचपन नहीं समझते हैं, फोटी फाइव-फिफ्टी फाईव कहना पड़ता है। इस स्थिति पर नवोदितजी को, जब वे घर पर अकेले होते हैं, गर्व भी है कि बच्चों का भविष्य बन रहा है। हासिल ये कि जिन्हें शिकायत है उन्हीं के घर से हिंदी बेदखल है। उम्मीद सारी जमाने से है। अभी तक कहा जाता था कि भगतसिंग सबको पसंद है पर पड़ौसी के घर में। अब हिंदी के लिए भी यही होता दिख रहा है। हमारा किसान भले ही अनपढ़ क्यों न हो लेकिन अगली फसल के लिए थोड़ा बीज बचा कर रखता है। किन्तु लेखकों ने साहित्य को सींचा पर भाषा की भ्रूण हत्या में शामिल हो गए। हरेक

किताबें खूब छप रही हैं लेकिन पढ़ने वाले हैं नहीं

नवोदितजी के तीन बच्चे हैं और तीनों अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे पैतालीस-पचपन नहीं समझते हैं, फोटी फाइव-फिफ्टी फाईव कहना पड़ता है। इस स्थिति पर नवोदितजी को, जब वे घर पर अकेले होते हैं, गर्व भी है कि बच्चों का भविष्य बन रहा है। हासिल ये कि जिन्हें शिकायत है उन्हीं के घर से हिंदी बेदखल है। उम्मीद सारी जमाने से है। अभी तक कहा जाता था कि भगतसिंग सबको पसंद है पर पड़ौसी के घर में। अब हिंदी के लिए भी यही होता दिख रहा है। हमारा किसान भले ही अनपढ़ क्यों न हो लेकिन अगली फसल के लिए थोड़ा बीज बचा कर रखता है। किन्तु लेखकों ने साहित्य को सींचा पर भाषा की भ्रूण हत्या में शामिल हो गए। हरेक को सरकारी या कापॉरेट नौकरियों में बच्चों की सुरक्षा दिख रही है। पैसा पहले, करियर बड़ा टारगेट, भाषा साहित्य का क्या है, दूसरे समझें। वो कहानी है ना जिसमें हर आदमी चुपके से दूध की जगह पानी डाल आता है, यह सोचते हुए कि बाकी तो दूध डालेंगे ही। स्कूल वही प्राथमिकता में होते हैं जो अंग्रेजी पर भारी दबाव रखते हैं और हिंदी बोलने पर प्रतिबंध और जुर्माना भी लगाते हैं। रही सही कसर घरों में निकल जाती है। राजधानियों, महानगरों में हिंदी ‘महरी की भाषा’ है, लिहाजा घरों में भी अंग्रेजी का जोर है। ड्राइंग रूम में बुक-केस की ओर देखें तो अंग्रेजी साहित्य दिखाई देता है। हिंदी साहित्य की किताबें रखने वाले पुराने बुकशॉप तो लगता है बंद ही हो गए। कहीं कोई होता भी है तो वहीं भी देसी-विदेशी अंग्रेजी लेखकों की किताबें सजी हैं और बिक भी रही हैं। एक साहब ने बताया कि उन्हें मजबूरन हिंदी की किताबों पर कवर चढ़ा कर रखना पड़ता है।



को सरकारी या कापॉरेट नौकरियों में बच्चों की सुरक्षा दीख रही है। पैसा पहले, करियर बड़ा टारगेट, भाषा साहित्य का क्या है, दूसरे समझें। वो कहानी है ना जिसमें हर आदमी चुपके से दूध की जगह पानी डाल आता है, यह सोचते हुए कि बाकी तो दूध डालेंगे ही। स्कूल वही प्राथमिकता में होते हैं जो अंग्रेजी पर भारी दबाव रखते हैं और हिंदी बोलने पर प्रतिबंध और जुर्माना भी लगाते हैं। रही सही कसर घरों में निकल जाती है। राजधानियों, महानगरों में हिंदी ‘महरी की भाषा’ है, लिहाजा घरों में भी अंग्रेजी का जोर है। ड्राइंग रूम में बुक-केस की ओर देखें तो अंग्रेजी साहित्य दिखाई देता है। हिंदी साहित्य की किताबें रखने वाले पुराने बुकशॉप तो लगता है बंद ही हो गए। कहीं कोई होता भी है तो वहीं भी देसी-विदेशी अंग्रेजी लेखकों की किताबें सजी हैं और बिक भी रही हैं। एक साहब ने बताया कि उन्हें मजबूरन हिंदी की किताबों पर कवर चढ़ा कर रखना पड़ता है। कुछ का मानना है कि सम्भावना गाँव और

कस्बों में है। वहाँ भारतीय संस्कृति अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हालाँकि टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, फटी जींस जैसी चीजें वहाँ पहुँच चुकी हैं। बात कुछ गरीबी की है कुछ संसाधनों की भी और सबसे बड़ी बात सोच की। स्कूल सरकारी हैं, बच्चे हिंदी बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं और घर परिवार में भी हिंदी है। आशावादी राहत के साथ बताते हैं कि हिंदी का पाठक यहाँ बसता है और भविष्य में हिंदी के लेखक भी यहीं से मिलेंगे। फोरीतौर पर कुछ उम्मीद जागती है। लेकिन हाल ही में एक संस्था के सर्वेक्षण से जो तथ्य सामने आये हैं वे उम्मीदों पर पानी फेरने वाले हैं। चौदह से अठारह साल के आठवीं कक्षा पास बच्चों में से एक चौथाई हिंदी की एक पंक्ति भी नहीं पढ़ पाते हैं। कई तो अपना नाम तक सही नहीं लिख पाते हैं! जबकि उनकी मातृभाषा और शिक्षा का माध्यम हिंदी ही है। आधे से अधिक गणित का मामूली सा सवाल भी हल करने में सक्षम नहीं हैं। दुनिया के नक्शे में भारत कहीं है यह बीस प्रतिशत को पता नहीं। अधिकांश पलकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं। साफ है कि शिक्षा उनकी प्राथमिकता में नहीं है। कुछ तो यह मानते हैं कि बच्चों को पढ़ा दो तो वे किसी काम के नहीं रहते हैं, नौकरी मिलती नहीं और खेती में मेहनत के काम वे करना पसंद नहीं करते। कहते हैं कि हर माह लाखों युवा रोजगार की तलाश में बाहर निकलते हैं लेकिन खराब शिक्षा के कारण उनकी तलाश

अंतहीन बनी रहती है। देश में शिक्षा कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनी। लोकतंत्र गरीबी के नाम पर ही पचहत्तर साल का हो गया। खराब हालात भ्रष्टाचार के लिए उर्वरा भूमि होते हैं। शिक्षा पर भारी बजट तो होता है लेकिन गुणवत्ता की ओर हमारा ध्यान नहीं होता है। पैसा आ रहा है और जहाँ उसे जाना है, जा रहा है। पिछले दिनों सोशल मिडिया पर एक वडियो चला था जिसमें कस्बाई स्कूलों के शिक्षकों के अज्ञान और मूर्खता को रेखांकित किया गया था। चालीस-पचास हजार रुपये वेतन लेने वाले कक्षा में सोते और समय काटते दिखाए गए थे। कुछ गुरुजन मदिरापान के साथ उपस्थित हो जाते हैं। निराशाजनक और आक्रोशित करने वाले इन संदेशों का लोगों ने मजा लिया जबकि ये चिंताजनक है। नगरों में बेरुखी झेल रही हमारी भाषा कुव्यवस्था के कारण कहीं भी ठौर नहीं पा रही है। ऐसे में हिंदी का भविष्य तलाशना कठिन काम है। सिर्फ हिंदी-सिनेमा का आभारी होने से बात बनने वाली नहीं है, कुछ हमें भी करना होगा। हिंदी अखबार और पत्रिकाएं अभी बाजार में हैं और कोशिश होना चाहिए कि ये भाषा और साहित्य बचाने में सहयोग करें। जिन्हें साहित्य की चिंता है उन्हें भाषा की चिंता भी करना पड़ेगी। बड़े पुस्तक मेलों, साहित्यिक उत्सवों, चर्चाओं-गोष्ठियों के साथ रोपणी के स्तर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भले ही अंग्रेजी एक जरूरी भाषा प्रतीत हो लेकिन हिंदी कमतर होने से बचना आवश्यक है।

नदी जोड़ी परियोजना

अनूप पौराणिक

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।



भारत के जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन और सतत विकास, हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। बुंदेलखंड के लिए, जो वर्षों से पानी की कमी और सूखे की मार झेलता आ रहा है, यह स्वप्न अब साकार होता दिख रहा है। ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ और ‘पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना’ इन क्षेत्रों में जल क्रांति का नया अध्याय लिखने जा रही हैं। इन ऐतिहासिक परियोजनाओं का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता को जाता है। साल 2002 में देश में सूखा और सिंचाई की गंभीर समस्या थी, जिसके समाधान के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ‘नदियों को जोड़ने’ का विचार प्रस्तुत कर भारत के भविष्य को नया दृष्टिकोण दिया था, लेकिन इसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ जाने के बाद योजना में कई अड़चने आईं और यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस सरकार के दौरान इस योजना पर कोई गंभीर काम नहीं हुआ। राहुल गांधी और उनके तमाम नेता बुंदेलखंड में विकास के ठोस काम करने के बजाय सिर्फ राजनीतिक पर्यटन करते रहे, पानी की समस्या से जुझ रहे किसान और आम जनता की ओर उनका ध्यान नहीं दिया। 2014 में केंद्र में सरकार बनते ही पीएम मोदी ने फिर से इस पर काम शुरू किया और ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी इस योजना के महत्व को समझा और उनकी तत्परता का ही परिणाम है कि अब उनके कार्यकाल के एक साल के अंदर अटल जी का सपना पूरा हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देखे इस सपने के साकार

भविष्य के लिए नई उपलब्धि का सिंचन करने वाले कदम

साल 2002 में देश में सूखा और सिंचाई की गंभीर समस्या थी, जिसके समाधान के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ‘नदियों को जोड़ने’ का विचार प्रस्तुत कर भारत के भविष्य को नया दृष्टिकोण दिया था, लेकिन इसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ जाने के बाद योजना में कई अड़चने आईं और यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस सरकार के दौरान इस योजना पर कोई गंभीर काम नहीं हुआ। राहुल गांधी और उनके तमाम नेता बुंदेलखंड में विकास के ठोस काम करने के बजाय सिर्फ राजनीतिक पर्यटन करते रहे, पानी की समस्या से जुझ रहे किसान और आम जनता की ओर उनका ध्यान नहीं दिया। 2014 में केंद्र में सरकार बनते ही पीएम मोदी ने फिर से इस पर काम शुरू किया और ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी इस योजना के महत्व को समझा और उनकी तत्परता का ही परिणाम है कि अब उनके कार्यकाल के एक साल के अंदर अटल जी का सपना पूरा हो रहा है।



बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास कर इस दिशा में कदम बढ़ाया है। परियोजना के लिए 44,608 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। इसमें केंद्र सरकार 90

प्रतिशत खर्च उठाएगी। बाकी 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। यह पीएम मोदी का वाजपेयी जी के अधूरे सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाली यह परियोजना न केवल बुंदेलखंड के लिए पानी की समस्या का समाधान करेगी, बल्कि इससे क्षेत्र की कृषि, उद्योग और रोजगार में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह परियोजना लगभग 13.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाएगी और 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएगी। वहीं 10 जिलों और 1900 गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि से जुड़ी गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और बुंदेलखंड से होने वाला पलायन रुकेगा। इसके अलावा, यह परियोजना बुंदेलखंड के वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी मददगार साबित होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व को जल आपूर्ति सुनिश्चित कर, यह क्षेत्र पर्यावरणीय संतुलन में भी योगदान देगा।

पार्वती, कालीसिंध, और चंबल नदियों को जोड़ने की यह परियोजना न केवल मध्यप्रदेश बल्कि राजस्थान के लिए भी वरदान साबित होगी। यह योजना हजारों गांवों में सिंचाई के साधन विकसित करेगी और जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में राहत प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता देकर यह सुनिश्चित किया है कि इसके माध्यम से क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। यह परियोजनाएं बुंदेलखंड और आपसपास के क्षेत्रों के लिए उम्मीद की नई किरण हैं। पानी की कमी से जूझते किसानों, पलायन करते युवाओं, और पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। ‘केन-बेतवा’ और ‘पार्वती-कालीसिंध-चंबल’ परियोजनाएं न केवल नदियों को जोड़ने का कार्य करेंगी, बल्कि दिलों और सपनों को भी जोड़ेगी। यह भारत के ग्रामीण इलाकों में समृद्धि और खुशहाली का नया अध्याय लिखेंगी। आज जब हम इन ऐतिहासिक परियोजनाओं की ओर देखते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के जीवन में नई उपलब्धि का सिंचन करेगा।

उपलब्धि

भूपेन्द्र गुप्ता

स्वतंत्र लेखक



नदी जोड़ी अभियान आज चर्चा का विषय है। इसका श्रेय सभी पार्टियों लेने की कोशिश भी करती हैं लेकिन इन परियोजनाओं का इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है। इस इतिहास को जानकर यह समझा जा सकता है कि सपनों के फलीभूत होने में सैकड़ों साल की तपस्या शामिल होती है। इसमें कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं है,बल्कि सरकारों के निरंतर और सकारात्मक प्रयास हैं। हालाकि गुलाम भारत मे 1900 के दशक में एक अंग्रेज इंजीनियर आर्थर कॉटन ने भारत की नदियों को जोड़ने की कल्पना की थी। उसका उद्देश्य था कि नदियों के अतिरिक्त जल से बड़ी-बड़ी नहरें बनाकर जल मार्गों की वृद्धि की जा सकती है जिससे ब्रिटिश सरकार को व्यापारिक सुविधा मिलेगी तथा दक्षिण भारत के तथा उड़ीसा के सूखे से निपटा जा सकेगा और वहां पर अतिरिक्त जल भेज कर उत्पादन में वृद्धि भी की जा सकेगी। किंतु इसमें आने वाले खर्च को देखकर ब्रिटिश हुकूमत भी आगे नहीं बढ़ी और यह ठंडे बस्ते में चली गई। देश आजाद हुआ और राष्ट्र निर्माण की योजनायें बननी शुरू हुईं। गरीबी संसाधनों के अभाव और तकनीशियनों की कमी से प्रथमिकतायें आगे बढ़ती गईं। आजादी के लगभग 23 साल बाद जब इंदिरा जी की सरकार में बांध बनाने वाले इंजीनियर डॉ. केएल राव सिंचाई मंत्री बने तब उन्होंने आर्थर काटन के इस सपने से धूल झाड़ी और इंदिरा जी के सामने रखा। कांग्रेस ने 1970 में इस योजना को नये दृष्टिकोण से जीवित किया। डॉ. केएल राव की सोच थी कि जो हिमालयीन नदियां हैं उनमें

आजादी के लगभग 23 साल बाद जब इंदिरा जी की सरकार में बांध बनाने वाले इंजीनियर डॉ. केएल राव सिंचाई मंत्री बने तब उन्होंने आर्थर काटन के इस सपने से धूल झाड़ी और इंदिरा जी के सामने रखा। कांग्रेस ने 1970 में इस योजना को नये दृष्टिकोण से जीवित किया। डॉ. केएल राव की सोच थी कि जो हिमालयीन नदियां हैं उनमें ग्लेशियरों के पिघलने के कारण गर्मियों में अतिरिक्त जल होता है और बाढ़ आती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं और उनमें बरसाती मौसम में बाढ़ आती है अतः हिमालयीन नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों की आपस में जोड़ दिया जाता है तो सूखे के मौसम में जल की उपलब्धता बनी रह सकती है इसे इंटर-वेसिन रिवर लिंकिंग कहा गया। इंदिरा गांधी ने 1980 में इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरडी की रिपोर्ट तैयार करवाई इसकी वित्तीय व्यवस्था बनाने के लिए शुरुआत की गई और उन्होंने 1982 में ‘नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी’ का निर्माण किया यह नदी जोड़ी अभियान का पहला कदम था इसके अंतर्गत इंटर-वेसिन नदियों को जोड़ने की योजनाओं पर कार्य शुरू हुआ। कई अध्ययन हुए, रिपोर्टें तैयार हुईं।



ग्लेशियरों के पिघलने के कारण गर्मियों में अतिरिक्त जल होता है और बाढ़ आती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं और उनमें बरसाती मौसम में बाढ़ आती है अतः हिमालयीन नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों की आपस में जोड़ दिया जाता है तो सूखे के मौसम में जल की उपलब्धता बनी रह सकती है इसे इंटर-वेसिन रिवर लिंकिंग कहा गया। इंदिरा गांधी ने 1980 में इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरडी की रिपोर्ट तैयार करवाई। इसकी वित्तीय व्यवस्था बनाने के लिए शुरुआत की गई और उन्होंने 1982 में ‘नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी’ का निर्माण किया यह नदी

जोड़ी अभियान का पहला कदम था। इसके अंतर्गत इंटर-वेसिन नदियों को जोड़ने की योजनाओं पर कार्य शुरू हुआ। कई अध्ययन हुए, रिपोर्टें तैयार हुईं। जब 1999 में एनडीए की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसे उलटकर योजना के पूरे स्वरूप को ही बदल दिया और इंटर-बेसिन परियोजनाओं को इंद्रा-वेसिन परियोजनाओं में बदल दिया किंतु 2003 तक यह विचार स्वरूप लेता इसके पहले ही 2002 में सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में पीआईएल लग गई।आगामी चुनाव में बाजपेयी सरकार उलट गई और 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन हुआ। तब इस परियोजना को फिर वास्तविक स्वरूप यानि इंटर- बेसिन योजना के रूप में जीवित किया गया तथा सरकार ने इस पर व्यापक अध्ययन करवाया। साल 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला दिया कि नदियों के इंटरलिंकिंग का फैसला नीतिगत है और इसे सरकारें ही करें। तब इस योजना के लिए 2012 से गति प्रदान की गई विभिन्न राज्यों के जल बंटवारे के आपसी समझौते और विवादों के निपटारे, पर्यावरणीय जोखिम एवं इकोसिस्टम को पहुंचने वाले नुकसानों के अध्ययन करते-करते

और सुलझाते-सुलझाते 2021 में केन बेतवा योजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिली जिसका भूमि पूजन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इंटर बेसिन नदी जोड़ी परियोजना मूलत आर्थर कॉटन का सपना था जिसे डॉ. केएल राव ने आगे बढ़ाया और इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान कर ‘राष्ट्रीय जल विकास अथॉरिटी’ का निर्माण किया और इस अथॉरिटी ने ही इस कल्पना को जमीन पर उतारने की शुरुआत की। संसाधन जुटाये, अध्ययन करवाया और यह योजना लगभग 54 साल बाद अब आकार ले रही है। आज देश में विकास को एक निरंतर अवधारणा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसका श्रेय अकेली एनडीए सरकार को देना आर्थर कॉटन के सपने के साथ भी धोखा होगा और डॉ. केएल राव तथा इंदिरा गांधी की संकल्पना के साथ भी बेईमानी होगी। विकास की योजनाओं की निरंतरता के लिए जिन-जिन लोगों ने काम किया है सभी सरकारों को श्रेय दें इसमें इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेई, मनमोहन सिंह एवं नरेंद्र मोदी सभी शामिल हैं। सपनों के जमीन पर उतरने की यही सच्चाई है।

जुआ-सट्टा सहित अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस का अभियान निरंतर जारी

जुए के फड़ पर पुलिस ने दी दबिश, 7 आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। पुलिस अधीक्षक निश्चल एन. झारिया के निर्देशन में खुले में शराब पीने वाले, फरार वारंटियों, जुआ-सट्टा और यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाही की जा रही है। खासकर जुआ-सट्टे के संचालन को लेकर पुलिस अधीक्षक का रवैया सख्त है।

एसपी निश्चल एन. झारिया ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को जुए-सट्टे और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए निर्देशित किया है। इसी तारतम्य में मुलताई पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस विभाग के पीआरओ से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोनापुर में बैरियर के पास नाले के समीप कुछ लोग टॉर्च की रोशनी में ताश के पत्तों पर पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। थाना प्रभारी मुलताई राजेश सातनकर ने योजना बनाकर टीम के साथ दबिश देकर मौके से राणा सिंह पिता प्रीतम सिंह बागरी (24) निवासी वरूड, रोशन पिता मधुकर गाडगे (21) निवासी वरूड, प्रणय पिता बामण सातपुते (25) निवासी शेघाट, प्रीतेश पिता सुनील मालवे (23) निवासी शेघाट, मोहित पिता बाबाराव ब्राम्हणे (24) निवासी जरूड, योगेश पिता किशन आठ्वरे (35) निवासी पाण्डा, थाना मोशी और संतोष पिता राजु उर्डके (30) निवासी वरूड को पकड़ा है। जिनसे 20,700 रुपये नगद और ताश के पत्ते, एक नग टॉर्च जब्त किये है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया एवं जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। इस कार्रवाई में थाना



प्रभारी मुलताई राजेश सातनकर, चौकी प्रभारी प्रभात पट्टन नेपाल सिंह ठाकुर, आरक्षक लक्ष्मीचंद, डुमनेश्वर कुमरे, विशाल चौरसिया, एवं सैनिक दिनेश रघुवंशी का विशेष योगदान रहा।

पुलिस ने किया स्थाई वारंटो को गिरफ्तार- रानीपुर पुलिस में जुवाड़ी निवासी हिमांशु अहलके को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

है। थाना प्रभारी अवधेश तिवारी ने बताया कि आबकारी एक्ट में पिछले 3 सालों से फरार चल रहे जुवाड़ी निवासी हिमांशु पिता रामेश्वर अहलके को थाना प्रभारी अवधेश तिवारी के मार्गदर्शन में एसआई भारत बौरासी, प्रेमलाल परते, आरक्षक सतीश वाडिवा ने जुवाड़ी से गिरफ्तार जेल भेज दिया है।

अज्ञात कारणों से महिला ने खाया जहर, मौत

बैतूल। एक महिला ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल चौकी प्रभारी सुरेन्द्र वर्मा के मुताबिक महिला दीना उर्डके पति राजेश (30) आमला थाना इलाके के हसलपुर की रहने वाली है। महिला का मायका बैतूल गंज थाना इलाके के बोड़ी बगलुड का है। महिला रविवार को ससुराल से अपने मायके आई हुई थीं। यहां उसने खेत जुताई पर लिया हुआ है, जिस पर काम करने आई थीं। मंगलवार रात उसने जहर खा लिया, जिसके बाद परिवार वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला ने जहर क्यों खाया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। अस्पताल पुलिस चौकी ने मर्ग डायरी गंज पुलिस को भेजी है। जिसकी जांच की जा रही है।

प्रवीण गुगनानी का किसान संघ ने किया अभिनंदन

शाल श्रीफल से किया सम्मानित

बैतूल। भारतीय किसान संघ, बैतूल जिला इकाई के सभी प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रवीण गुगनानी को अटल बिहारी स्मृति सम्मान एवं एक लाख रुपये की सम्मान राशि प्राप्त होने पर बधाई दी है। मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रवीण गुगनानी की पुस्तक स्वप्न ही तो है कविता के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर किसान संघ के संभागा संगठन मंत्री दिनेश शर्मा, प्रांत पदाधिकारी पुरुषोत्तम



सरले, और अमर दास चौधरी ने प्रवीण गुगनानी के कार्यालय पहुंचकर उन्हें शाल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं किसान संघ के विभाग संगठन मंत्री दिनेश शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अखिल भारतीय स्तर का यह अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान किसान संघ के एक कार्यकर्ता को मिलना संगठन के लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि सम्मान की राशि साहित्य परिषद को समर्पित कर प्रवीण गुगनानी ने समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। दिनेश शर्मा ने किसान संघ की ओर से प्रवीण गुगनानी को शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि भविष्य में भी वह अपनी लेखनी के माध्यम से संगठन के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने प्रवीण गुगनानी की उपलब्धि की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। किसान संघ की इस सहाभागिता से कार्यक्रम ने एक यादगार रूप ले लिया।

धड़कन शाह ने कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

बैतूल। बैतूल की धड़कन शाह ने साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। धड़कन ने अपनी खेल पहुंचने पर जोड़ार स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन से घर तक जूलूस निकाला गया। साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में कराटे की प्रतियोगिता में उनका पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से हुआ था। जिसे उन्होंने 5-0 से अपने नाम कर लिया था। इसके



बाद दूसरा मुकाबला बोत्सवाना, तीसरा केन्या और चौथा ऑस्ट्रेलिया से हुआ। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड हासिल किया। सभी मैच 53 किलोग्राम वर्ग में हुए थे। इस मौके पर धड़कन ने अपनी खेल उपलब्धियों के लिए परिवार वालों और कोच की विशेष भूमिका बताई है। इसके पहले धड़कन ने भूटान में आयोजित साउथ चैम्पियनशिप में भी गोल्ड जीता था। हाल ही में उसने इंदौर में आयोजित नेशनल चैम्पियनशिप में भी गोल्ड जीता है। धड़कन 2016 से कराटे की प्रैक्टिस कर रही है। 2023 में राज्य खेल एकेडमी में कराटे ट्रेनिंग के लिए उनका चयन हुआ था। तब से वह भोपाल में ही प्रैक्टिस कर रही है।

जनपद

गोंडी लोकनृत्य में बिखरे परंपरा के रंग

माथनी में गोंडी लोकनृत्य और फिल्मी डांस प्रतियोगिता का सफल आयोजन

बैतूल। ग्राम माथनी में नव युवा समिति के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय गोंडी लोकनृत्य और फिल्मी डांस प्रतियोगिता का समापन हुआ। यह दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 23 दिसंबर की शाम शुरू हुआ था, जिसमें गोंडी परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मेल देखने को मिला। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गोंडी संस्कृति का संरक्षण और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम में 17 गोंडी लोकनृत्य दल और 25 एकल कलाकारों ने भाग लिया। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल सहित अन्य क्षेत्रों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीता। इस आयोजन में 1000 से अधिक दर्शक उपस्थित थे, जो इसकी सफलता और भव्यता को दर्शाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. योगेश पंडाग्रे (विधायक) ने नव युवा समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए गोंडी संस्कृति के संरक्षण का महत्व



बताया। मुख्य वक्ता डॉ. राजा धुर्वे (संचालक, एमसीआई बैतूल) ने शिक्षा और जागरूकता पर जोर दिया। अन्य विशिष्ट अतिथियों में जामवंत सिंह कुमरे (जयस प्रदेश संयोजक), जिला पंचायत सदस्य संगीता श्याम परते, जनपद सदस्य प्रमिला मूलचंद वर्मा, सरपंच समी मंतू सलाम, उपसरपंच सुमंत्रा सरकार इवने और जनपद सदस्य अरविंद वरकड़े उपस्थित रहे। ग्राम के वरिष्ठ मार्गदर्शकों, प्रेम मसंकोले, गंगाराम मसंकोले, मनोहर तुमड़म, सुमरत उर्डके और धम्पू उर्डके ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता के निष्पायक मंडल में ओम म्यूजिक जॉन के निदेशक ओम प्रधान, राजेंद्र इरपाचे और बादल इरपाचे शामिल थे। प्रथम स्थान झुलवाई डांस ग्रुप महतपुर दामजीपुरा, द्वितीय स्थान- बीपी डांस ग्रुप छतरपुर, तृतीय स्थान, डीपी ट्राइबल डांस ग्रुप माथनी। फिल्मी डांस में प्रथम स्थान राजकुमारी उर्डके कॉलेजिया चोपना, द्वितीय स्थान सत्यम वट्टी छिंदवाड़ा, तृतीय स्थान रूही सलाम बैतूल सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के अध्यक्ष दिलप्रकाश तुमड़म ने बताया कि यह आयोजन लगातार 5 वर्षों से किया जा रहा है। उपाध्यक्ष करन उर्डके और सदस्य राजू उर्डके, संजु उर्डके, राहुल मसंकोले, अजय मसंकोले, मधुकर धुर्वे, मुकेश धुर्वे, सतीश परते, शिवशंकर उर्डके, राकेश उर्डके, परेश धुर्वे, अमित इवने, बबू धुर्वे, राजकुमार इवने और शिवा इरपाचे सहित अन्य सदस्यों ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कार्यक्रम गोंडी संस्कृति को संरक्षित करने और ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करने का माध्यम बना। समिति ने भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों की प्रतिबद्धता जताई है, ताकि ग्रामीण समाज अपनी परंपराओं से जुड़ा रह सके और नई प्रतिभाओं को मंच मिलता रहे।

सुशासन दिवस पर जिला कार्यालय में लगी प्रदर्शनी

जिले के 30 संगठनात्मक मंडलों में बूथ स्तर पर मनाई गई अटलजी की जन्म जयंती

बैतूल। भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100 वीं जयंती के शताब्दी समारोह को जिला भाजपा द्वारा सुशासन दिवस के रूप में जिले में बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में अटलजी के जीवनवृत्त पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में अटल जी के राजनैतिक जीवन और निर्णयों को दिखाया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व सांसद सुभाषा आहूजा, ज्योति धुर्वे, पूर्व जिलाध्यक्ष शिवप्रसाद राठीर, विधायक हेमंत खंडेलवाल ने फिता काटकर किया। तत्पश्चात अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। प्रदर्शनी के संयोजक जिला मंत्री अतीत पंगार ने बताया कि अटल जी की 100 वीं जन्म जयंती पर संगठन जन्मशताब्दी वर्ष मना रहा है। इसी क्रम में अटल जी के संगठन और सरकार के कार्यों का वर्णन प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, वरिष्ठ नेता रमेश मिश्रा, नपाध्यक्ष पार्वती बारस्कर,अंशुमान बचले, सीरभ राघव सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, नगर मंडल के कार्यकर्तागण उपस्थित थे।

बैतूल में 27 को होने वाला सीएम का कार्यक्रम फिर निरस्त

बैतूल। 27 दिसंबर को बैतूल में स्वामित्व योजना के तहत आवासीय पट्टे के वितरण का वृहद कार्यक्रम होना था। जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भाग लेने वाले थे, लेकिन यह कार्यक्रम निरस्त हो गया है। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अब 27 को बैतूल में नहीं होगा। एक प्रशासनिक अधिकारी ने भी बताया कि कार्यक्रम निरस्त हो गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वचुंअली जुड़कर हितग्राहियों से संवाद करना था। संभावना है कि अब यह कार्यक्रम अन्य किसी जिले में आयोजित होगा। गौरतलब रहे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करने की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें 27 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को तैयारी में जुटने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शाम होते-होते खबर आई कि यह कार्यक्रम बैतूल में निरस्त हो गया है। इसके पहले बैतूल में 19 दिसंबर को सीएम का कार्यक्रम होना था, लेकिन वह भी निरस्त हो गया था। 27 दिसंबर के कार्यक्रम की सूचना खुद प्रशासन ने दी थी, लेकिन अब यह भी कैसिल हो गया है।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है : राजीव खंडेलवाल



अटल जी के विचारों को आत्मसात करें कार्यकर्ता: बबला शुक्ला- आज हम भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100 वीं जयंती मना रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता अटल जी के जीवन पर आधारित विचारों को

आज आत्मसात करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। उक्त उद्गार भारतीय जनता पार्टी के बडोरा मंडल के दोनरा बूथ क्रमांक 46 पर आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला ने व्यक्त करते हुए कहा कि अटल जी ने अपना

बच्चों को जिताने शिक्षक ने बहाया पसीना

बैतूल। विगत दिनों एमएलबी स्कूल में आयोजित विज्ञान गणित व पर्यावरणीय जिला स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें स्कूल, संकुल व ब्लॉक स्तर से विजेता छात्राओं व मार्गदर्शक शिक्षक ने शामिल होकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। छेड़वाड़ा स्कूल के छात्र सत्यम कुंभारे, दिव्यांशी परिहार ,रूपाली पाटनकर व शिक्षक मदनलाल डडोरे, शारदा माथनकर ने लगातार मेहनत कर त्रिकोणमिति उद्यान पर गणितीय मॉडल बनाकर जिला स्तरीय प्रदर्शनी में अच्छा प्रदर्शन किया गया । जिसके तहत मॉडल का संभागा के लिए चयन हुआ । अब बच्चे संभागा स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, जातृत्व

हो की रविवार को छात्र व शिक्षकों को समय पर प्रदर्शनी में पहुंचना था। परंतु गाड़ी शराब होने के कारण समय पर प्रदर्शनी में पहुंचने के लिए भूथ्यों की व्यवस्था नहीं होने के चलते शिक्षक मदनलाल डडोरे ने बड़ा मॉडल होने के चलते रास्ते में कार खराब होने के कारण अपना मॉडल सिर पर उठाकर लगभग 1 किमी पैदल लेकर पहुंचे। उपस्थित शिक्षकों व अधिकारियों ने यह नजारा देखा तो सभी ने शिक्षक के इस प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि हर शिक्षक ईमानदारी, कर्मठता और मेहनत के साथ काम करें तो निश्चित ही अवसर पर अनेक शिक्षक साथी अधिकारी कर्मचारी छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

अब बैतूल में भी थ्रीडी पर फिर धूम मचाएगी पुष्पा-2

25 दिसम्बर से कांतिशिवा मल्टीप्लेक्स में होगा प्रदर्शन

बैतूल। अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब हासिल कर पुष्पा 2 मील का पथर बन गई है। बीते रविवार को पुष्पा 2 ने दमदार कमाई कर बाहुबली 2 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह फिल्म बैतूल की कांतिशिवा टॉकीज सहित देश और प्रदेश के



चुनिंदा सिनेमाघरों में ही थ्रीडी में दिखाई जाएगी। बैतूल जिले में भी पुष्पा-2 फिल्म का व्यापार जमकर है। लोग पुष्पा-2 फिल्म देखने के लिए लगातार सिनेमाघर पहुंच रहे हैं। उसीद की जा रही है कि पुष्पा-2 पसंद करने वाले थ्रीडी इफेक्ट में भी फिल्म का मजा जरूर लेंगे। कांतिशिवा मल्टीप्लेक्स के प्रबंधक ने बताया कि श्री डी इफेक्ट के साथ फिल्म के शौकीनों को पुष्पा-2 देखने के लिए सिर्फ कांतिशिवा मल्टीप्लेक्स में ही सुविधा मिलेगी। यह फिल्म देश और प्रदेश के चुनिंदा सिनेमाघरों में ही थ्रीडी इफेक्ट के साथ दिखाई जाएगी। बता दें कि पुष्पा-2 अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब हासिल कर चुकी है। बीते रविवार को पुष्पा 2 ने दमदार कमाई कर बाहुबली 2 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह फिल्म बैतूल की कांतिशिवा टॉकीज सहित देश और प्रदेश के चुनिंदा सिनेमाघरों में ही थ्री डी में दिखाई जाएगी।

पारसनाथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा

धार। दिगम्बर जैन पारसनाथ अतिथ्य तीर्थ क्षेत्र आहूजी में 26 दिसंबर को भगवान पारसनाथ का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रबंध समिति के अध्यक्ष वीरेन्द्र जैन एवं सचिव राकेश गंगवाल के अनुसार होने वाले कार्यक्रमों में प्रातः 7 बजे भगवान के अभिषेक एवं शांतिधारा, प्रातः 8 बजे नित्य पूजन एवं पारसनाथ मंडल विधान पूजन, प्रातः 10 बजे भव्य शोभायात्रा, 11 बजे अतिथि उद्बोधन, सम्मान एवं संत प्रवचन होंगे। अंत में श्रीजी के जन्माभिषेक एवं महाआरती होगी। मीडिया प्रभारी सुभाष जैन ने बताया कि जन्मोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, विहिप के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुकुमचंद सांवला, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी, दानवीर भूमि प्रदाता गजेन्द्र जैन गिरी गुप शामिल होंगे। संपूर्ण कार्यक्रम को आचार्य विप्रणतसागरजी मसा एवं मानतुंगगिरी तीर्थ क्षेत्र की संचालिका श्रीमती चंद्रमति माताजी का सान्निध्य मिलेगा। दिगम्बर जैन समाज के अध्यक्ष श्रेणिक गंगवाल एवं आहू प्रबंध समिति अध्यक्ष वीरेन्द्र जैन ने बताया कि कार्यक्रम में समाजजनों के अतिरिक्त मप्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से भक्त शामिल होंगे।

सीएम राइज आमला के विद्यार्थियों ने किया औद्योगिक भ्रमण



आमला। नगर के सीएम राइज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमला के व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत संचालित इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी [आईटी] के 52 विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में मंगलवार दिनांक 24 दिसंबर 2024 को प्राचार्य डॉ राजेश कुमार खैरवाल के निर्देशन में औद्योगिक भ्रमण अंतर्गत शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज सोनाघाटी बैतूल का भ्रमण किया। पालीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य श्री अरुण भदौरिया एवं शिक्षक साथियों श्री गोरखेदे, एवं श्री किशोर झरबड़े द्वारा विद्यार्थियों को समस्त प्रायोगिक लेबोरेट्री का भ्रमण कराया गया एवं महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। भविष्य में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पालीटेक्निक कॉलेज में प्रवेश एवं रोजगार के विकल्प इत्यादि की जानकारी प्रदान की गई। छात्रों ने समस्त इकाइयों का भ्रमण किया अपने मन मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों को पूछा एवम उनका समाधान पा कर प्रफुल्लित हुए। इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी श्री प्रदीप नागले, प्रशिक्षक श्री कृष्णा सूर्यवंशी [आईटी/आईटीएस], श्री परवेज आलम, श्रीमती ज्योति सोनी, श्रीमति जुली उमाटे ने अपनी सहभागिता प्रदान की।

पांच लाख की लागत से होगा सांस्कृतिक चौपाल निर्माण कार्य

बैतूल। आमला विधानसभा के ग्रामों में 5 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति से सांस्कृतिक मंच चौपाल निर्माण कार्य किए जाएंगे। जारी आदेश के अनुसार घोड़ाखेरी विकासखंड की ग्राम पंचायत कोलगांव के ग्राम जाजलपुर में माता मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच चौपाल निर्माण कार्य 2 लाख 50 हजार की लागत से किया जाएगा। इसी प्रकार घोड़ाखेरी विकासखंड की ग्राम पंचायत कोलगांव के ग्राम मझकाढाना में हनुमान मंदिर के पास 2 लाख 50 हजार की लागत से सांस्कृतिक मंच चौपाल निर्माण कार्य किया जाएगा। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत कोलगांव को योजना के तहत निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

गांधी वार्ड में 52 हजार 762 रुपए की लागत से होगा टीन शेड निर्माण कार्य

बैतूल। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की स्वेच्छानुदान निधि से बैतूल बाजार के गांधी वार्ड में टीन शेड निर्माण कार्य किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार बैतूल बाजार के गांधी वार्ड में 52 हजार 762 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति से टीन शेड निर्माण कार्य किया जाएगा। इस निर्माण कार्य में विधायक निधि से 50 हजार की राशि एवं 2 हजार 762 की राशि नगर पालिका द्वारा वहन की जाएगी।

अटल जी दूरदृष्टि के नायक थे, संगोष्ठी संपन्न

बैतूल। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र माय भारत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संगोष्ठी व शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम वीवीएम कॉलेज से प्रो.एसआर गायकवाड व छात्रावास अधीक्षक सुरेश कनाटे व राधेकाल बनखेडे के आतिथ्य में और धनंजय सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर संगोष्ठी में सुरेश कनाटे ने कहा कि अटल जी के किए हुए कार्यों को आज हम विकास की दृष्टि से धरातल पर देख रहे चाहे वह नदी जोड़ो अभियान हो, चाहे गांव से गांव जोड़ो अभियान हो, जय जवान जय



किसान जय विज्ञान हो। उन्होने कहा कि अटल दूरदृष्टी के नायक थे। श्री गायकवाड जी अटल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के युवाओं को अटल जी के इन आचार विचार व भाव के साथ पठकर विशेष जीवन में उतारने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। माय भारत पोर्टल की जानकारी से धनंजय सिंह ठाकुर ने अगगत करायी और कहा कि अटल जी हमारे लिए सदैव युगपुरुष प्रेरणा पुरुष के तौर रहेंगे। इस अवसर पर खेल युवा कल्याण विभाग से रामनारायण शुक्ला, जन अभियान परिषद से इंद्रदेव कावडकर, संजय कुमार, सुशील उदयपुरे आदि मौजूद थे।

अटलजी ने सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण का स्वप्न देखा था, आज वह मोदी के नेतृत्व में साकार होने की तरफ अग्रसर है : पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा

पूर्व प्रधानमंत्री अटलजी की 100वीं जन्म जयंती पर जिले में प्रत्येक मंडल के बूथों केंद्रों पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया

धार। भाजपा जिला संगठन ने 25 दिसम्बर पर पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, अटलजी की जन्मजयंती पर सुशासन दिवस के रूप में जिले के प्रत्येक मंडल तथा बूथों केंद्रों पर आयोजन हुआ। धार नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल निगम और जयराज देवड़ा एवं भाजपा पदाधिकारियों ने अटलजी की सरकार में कार्य करने वाले पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री रहे वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा के निवास पहुंचकर शाल श्रीफल से सम्मानित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने बदनावर विधानसभा के ग्राम नागदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क पर सुशासन यात्रा निकाल कर पूर्व अटलजी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा विधायक नीना वर्मा और कालु सिंह ठाकुर, सुशासन दिवस कार्यक्रम जिला संयोजक विश्वास पांडे, भाजपा नेता जिला पदाधिकारी सभी मंडल अध्यक्ष समेत बृथ अध्यक्षों ने अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर सुशासन दिवस के रूप में मनाया। पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री विक्रम वर्मा ने कहा कि अटलजी ने जिस सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण का स्वप्न देखा था, आज वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में साकार होने की तरफ अग्रसर है।



भाजपा सरकार अनेक जन हितैषी योजनाओं को संचालित कर रही है। अटलजी ने अपना संपूर्ण जीवन सत्ता और संगठन एवं भारत के विकास के लिए व्यतीत किया वे साहित्य के क्षेत्र में भी जिन्होंने अपनी मधुर राष्ट्र भक्ति की कविताओं के माध्यम से हम सबको नई प्रेरणा

दी लोकसभा में जब अटलजी का उद्बोधन होता था तो विपक्ष के लोग दंग रह जाते थे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री विक्रम वर्मा को सम्मानित करने के अवसर पर भाजपा नेता प्रभु राठौर, पूर्व जिला महामंत्री उमेश गुप्ता, जिला

कार्यालय मंत्री जगदीश जाट जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल निगम और जयराज देवड़ा, मनीष प्रधान, दीपक बिड़कर, विपिन राठौर, नितेश अग्रवाल सहित भाजपा नगर पदाधिकारी बृथ अध्यक्ष एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

किसानों को नई टेक्नोलॉजी से बने नये-नये यंत्रों का उपयोग करना चाहिए : विधायक मलैया खजुराहो में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा व सुना

दमोह। पानी बहुत बड़ी चीज है, पहले प्रदेश के अंदर 07 से 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी धीरे-धीरे सिंचाई बड़ी और उसके बाद सिंचाई का रकबा बढ़ता गया, अब 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हो गया है। इस आशय की बात पूर्व मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन एवं कृषि विज्ञान मेले के दौरान कही। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती और भगवान बलराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर नितेन्द्र सिंह लोधी, हरिश्चंद्र पटेल, नर्मदा सिंह एकता, श्रीराम पटेल, पूरन पटेल, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एसडीएम दमोह आरएल बागरी, उप-संचालक कृषि जितेन्द्र सिंह राजपूत मंचासीन रहे।



सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी के चरणों में नमन किया। श्री मलैया ने कहा उनके साथ रहकर छोटी-छोटी बातें सीखने का बहुत अवसर मिला। प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे किसान सत्यपाल पटेल ने कहा सुपर सीडर में कृषि अभियांत्रिकी की तरफ से 1 लाख 5 हजार का अनुदान मिला है, उससे स्वयं की बोनी भी की है और किराए पर भी चलाया है। उन्होंने कहा नई-नई मशीनों का किसानों को पता चलता है, तो उससे उत्पादन भी बढ़ेगा और भविष्य में किसानों को लाभ भी होगा। इसी प्रकार तेंदूखड़ा के ग्राम बोरिया से आये बलवंत यादव ने कहा यहां पर मेला लगा हुआ है, यहां पर अनुदान पर कृषि यंत्र रखे हुए हैं जिन किसानों को यह यंत्र लेने हैं, उसके बारे में सभी कुछ बताया गया है। इसी प्रकार सीता नगर सरपंच नरोत्तम पटेल ने कहा मेले में बहुत सारे कृषि के यंत्र, जैविक दवाई, जैविक उत्पाद, सहित विभिन्न कृषि यंत्रों

की प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जो आधुनिक खेती के लिए फायदेमंद है। इनका सिस्टमैटिक उपयोग करें तो किसान खेती को दोगुना कर सकता है। इसी प्रकार एग्रोदूत कंपनी के को-फाउंडर ने कहा एग्रोदूत एक एआई पर आधारित एक नई तकनीक हैं, जिससे किसानों को बुवाई से लेकर कटाई तक के सारे सॉल्यूशन एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं, किसान आम भाषा में सवाल पूछ कर अपनी भाषा में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा यह सारे के सारे प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अवसर पर हरिश्चंद्र गुड्डा पटेल, नर्मदा सिंह एकता, श्रीराम पटेल, उप संचालक कृषि जितेन्द्र सिंह राजपूत ने अपनी-अपनी बातें विस्तार से रखीं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, निजी कस्टम हायरिंग, पावर स्प्रेयर, मृदा हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत नवीन निर्मित आर्बिट्रिट प्रयोगशाला सहित अन्य किसानों की अतिथियों द्वारा हितलाभ वितरण किये गए।

स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा जीवन बचाने एकजुटता जरूरी

दमोह। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई जी के 100 वे जन्म दिवस पर प्रशंसक जिले के वरिष्ठ पत्रकार अटल राजेन्द्र जैन द्वारा जिला चिकित्सालय में रक्तदान किया गया। अटल जी की जन्म जयंती पर रक्तदान को प्रेरित करते अटल राजेन्द्र जैन ने कहा कि रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है। रक्तदान के प्रयास में सभी को शामिल होने का आह्वान किया। स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा जीवन बचाने और एकजुटता बढ़ाने में निभाई जाने में भूमिकाओं की ओर ध्यान आकर्शित किया जा सके। इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसायटी के प्रदेश प्रतिनिधि कृष्ण कुमार परोह, आल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष समाजसेवी महेन्द्र जैन सोमखेड़ा, लघु व्यापारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तनुज पाराशर, आर एम ओ डॉक्टर चौधरी, विनोद, अनुपम खरे, मनीष सागर, ब्रजेश अट्ट्या की उपस्थिति रही। आज ही महामाया रक्तदान समिति के अध्यक्ष अखिलेश रजक ने भी 33 बी बार रक्तदान किया और सभी से रक्तदान करने की अपील की।



ग्रामीण महिलाओं ने लाइली बहना योजना चालू करने के लिए सौंपा ज्ञापन चिचोली में किया प्रदर्शन, सीएम से वादों को पूरा करने का आग्रह

बैतूल। चिचोली ब्लॉक के ग्राम चुनाव हजुरी की 50 महिलाओं ने लाइली बहना योजना को पुनः चालू करने और फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश काकोडिया, आदिवासी महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पा पेंटराम, चिचोली ब्लॉक ग्रामीण अध्यक्ष नैकराम यादव और ग्रामीण महिला अध्यक्ष ने महिलाओं की मांगों का समर्थन किया। महिलाओं ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि जिन बहनों के फॉर्म अब तक नहीं भरे गए हैं, उनके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ है। महिलाओं का कहना है कि यदि एक महीने के भीतर लाइली बहन योजना के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे जिला मुख्यालय जाकर ज्ञापन सौंपेंगी और भूख हड़ताल पर बैठेंगी। महिलाओं ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा कि



शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रैलियों में जो वादे किए थे, वे सभी अधूरे रह गए हैं। ज्ञापन देने वालों में कंचना बारस्कर, लक्ष्मी यादव, सुखमणी यादव, रेखा यादव, फूलवती यादव, सरोज राठौर, कांति वाघमारे, किरण वाघमारे,

रामवती वरकडे, राधिका वरकडे, मुन्नी परते, मनौती धुर्वे, सुखिया धुर्वे, फूलवती ऊर्दके, बसंती परते, बिंसादी, कविता, गीता, श्याम, शारदा, सुखवती, अंजीरा, सेवती, नरबदी, शीतल, अनीता, कृष्णा, पंकी, रीना, सरिता,

ललिता, बसंती, और कमलती सहित अन्य महिलाएं शामिल थीं। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगी।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी के निधन पर व्यक्त किया शोक

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सतना जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री विष्णुकांत त्रिपाठी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को यह असौम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने को ईश्वर से प्रार्थना की है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, अजय कुमार बोकिल, आयु 67 वर्ष निवासी ई 18, 45 बंगले, बोर्ड टी.टी.नगर भोपाल, इसी नाम से जाना जाता रहा हूं। अब मैं अपना नाम आधार कार्ड के अनुसार परिवर्तित कर अजय बोकिल कर रहा हूं। जिसका उद्देश्य मेरे विभिन्न अविवार्य दस्तावेजों जैसे कि पासपोर्ट आदि में नाम की एक समानता रहे। नाम में यह परिवर्तन मेरे द्वारा दि. 24/12/2024 को भोपाल में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार है।

अजय बोकिल, भोपाल

